● सीधी, सिंगरौली, रीवा एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित ● website-https://vindhyatiger.in ● epaper-https://epaper.vindhyatiger.in ● वर्ष : 36, अंक 164, पृष्ठ : 08, सीधी, बुधवार, 24 जुलाई 2024 - मूल्य : 2.00 रुपया मात्र

दैनिक समाचार पत्र

# विन्ध्य टाइगर

हक की बात, बुलंदी के साथ

अशोक गहलोत की फ्री स्मार्टफोन योजना स्थगित 5

अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान 6

## 64 हजार महीने तक की कमाई टैक्स के दायरे में नहीं

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए नई कर प्रणाली के टैक्स स्लैब में बदलाव का एलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि नई दरों के अमल में आने से देश के करीब चार करोड़ करदातओं को आयकर के मद में 17500 रुपये तक का लाभ होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50 हजार रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है। नई कर प्रणाली के तहत तीन लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री रखा गया है। हालांकि, सात लाख रुपये तक की आमदनी वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसका कारण हम आपको आगे बताएंगे। पहले जानिए इस बार टैक्स दरों में क्या बदलाव किया गया? वित्त मंत्री के बजट में किए गए एलानों के बाद अगर किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास है तो उसे नई कर प्रणाली में कोई आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है। बजट से पहले की स्थिति में सालाना आमदनी 7,50,000 रुपये तक रहने पर ही करदाता को टैक्स देने से राहत मिलती थी।

भले ही नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री है लेकिन सात लाख तक कमाने वाले को भी टैक्स नहीं देना होता है। इसका कारण है इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट। धारा 87ए के अनुसार, किसी व्यक्ति की टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये होने पर उसे टैक्स में छूट दी जाएग और उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

अगर किसी करदाता की आमदनी 8 लाख 50 हजार रुपये सालाना है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7,75,000 हजार रुपये रह जाती है। नई कर प्रणाली के तहत नई दर के अनुसार उसे आयकर के रूप में 27500 चुकानें पड़ेंगे। पुरानी दरों के आधार पर उक्त करदाता की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये मानी जाती। ऐसे में उसे पुरानी दरों के हिसाब से उसे 35000 रुपये कर के रूप में चुकाने होते। इस तरह वित्त मंत्री के स्लैब बदलने के एलान के बाद अब करदाता को 7,500 रुपये की बचत होगी। इसी गणना के आधार पर मान लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की 75 हजार रुपये की राशि घटाने के बाद किसी करदाता की आमदनी 9,75,000 रुपये है, तो उसे उपरोक्त गणना के हिसाब से 47,500 रुपये कर चुनाना पड़ेगा। पुरानी स्थिति में उक्त करदाता की आमदनी 50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अनुसार 10 लाख रुपये सालाना मानी जाती। ऐसे में उन्हें 60 हजार रुपये आयकर मद में चुकाने पड़ते। इस तरह करदाताओं को नई दरों के एलान के बाद 12,500 रुपये बचेंगे।

अब मान लीजिए किसी करदाता की आमदनी इस बार के बजट में हुए एलानों से पहले 15 लाख 50 हजार रुपये थी। तो उसे आयकर की गणना के अनुसार 1,50,000 रुपये कर चुकाने पड़ते। अब सरकार सरकार के नए एलानों के बाद उसी करदाता की आमदनी 14 लाख 75 हजार रुपये मानी जाएगी और उसे कर के रूप में 1,35,000 रुपये चुकानी पड़ेगी।

## आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति

मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति

उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं।

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।

## विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित है बजट : मुख्यमंत्री

किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है बजट

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित केन्द्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। बजट में दैदिप्यमान भारत का भाव और महंगाई दर पर नियंत्रण की भावना स्पष्टत: परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केन्द्रित है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश को भी विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाने का मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्यप्रदेश की संभावना निहित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से महंगाई दर पर कन्ट्रोल करने की भावना है, वो परिलक्षित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक और महंगाई दर में स्थिरता हासिल की गई है। यह बजट भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है। नयी टैक्स रिजीम में स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50 हजार से 75 हजार रुपये, मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए करने तथा 30 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज करने का निर्णय ऐतिहासिक है।

## द्वारका में बाढ़, एयरफोर्स ने 3 किसानों को रेस्क्यू किया

**नई दिल्ली।** गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। द्वारका के पनेली गांव में बाढ़ में फंसे 3 किसानों को एयरफोर्स ने हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया। द्वारका में 12 घंटे में 281 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां आज भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 200 मिमी बारिश दर्ज की गई। आपात स्थिति से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की 3 टीमें तैनात की गई हैं।

## प.बंगाल के साउथ 24 परगना में सुरंग मिली

गवर्नर बोले- बांग्लादेश बॉर्डर के पास टनल मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा

**कोलकाता।** पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के एक घर में पुलिस को एक सुरंग मिली थी। यह सुरंग बांग्लादेश की बॉर्डर के करीब है। इसे लेकर गवर्नर आनंद बोस ने ममता सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने कहा है कि बॉर्डर के पास के घर में सुरंग निकलना देश के लिए खतरा है। ममता बनर्जी सरकार को मजबूत और निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है।

दरअसल, 15 जुलाई को पुलिस ने सद्दाम नाम के शख्स के घर पर छापा मारा था। सद्दाम नकली सोने के मूर्ति का डीलर है। उसके घर पर मिली 40 मीटर लंबी सुरंग नहर की ओर निकलती है। इस नहर से नाव के सहारे मतला नदी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से बांग्लादेश सीमा को पार किया जा सकता है। पुलिस का मानना है कि सद्दाम ने सुरंग का इस्तेमाल छापेमारी के दौरान भागने के लिए भी किया था।

पुलिस को सोशल मीडिया पर नकली सोने की मूर्तियों से जुड़ी धोखाधड़ी और खरीदी गई वस्तुओं की डिलीवरी न होने की कई शिकायतें मिली थीं। इस पर पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची। लेकिन पुलिस सद्दाम समर्थकों से पत्थरबाजी और विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके बाद पुलिस लौट आई और उसी दिन शाम को फिर छापेमारी कर सुरंग का पता लगाया। पश्चिम बंगाल के राजभवन ने गवर्नर के हवाले से एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा सुंदरबन में मिलने वाली नहर से जुड़ी सुरंग का मिलना देश के सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

## सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत मिली

**बेंगलुरु।** बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार (23 जुलाई) को जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत दी है। सूरज को दो लोगों की जमानत और 2 लाख रुपए का निजी बांड भरने को भी कहा गया। कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि है कि सूरज को जांच में पूरा सहयोग देना होगा। जब भी जांच अधिकारी बुलाए तो आना होगा। अदालत में अपना पासपोर्ट पेश करना होगा और अदालत से लिखित अनुमति के बिना कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते हैं।

## जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ शुरू

सुरक्षाबलों में 3 आतंकियों को घेरा, पुंछ में 1 जवान घायल

**जम्मू।** जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप सुरक्षाबलों के घेरे में है। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर कर थे। सुरक्षाबलों को कुपवाड़ा के लोलाब के त्रुमखान इलाके में आतंकियों के होने इनपुट मिला था इस पर सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल दोनों ओर से गोलाबारी जारी है। इससे पहले पुंछ में एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर में मंगलवार (23 जुलाई) सुबह करीब 3 बजे आर्मी-आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया।

22 जुलाई को सुबह करीब 3 बजे राजौरी के घोंधा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने एक आतंकी को मार गिराया था। इस हमले में एक जवान और परशोत्तम के चाचा घायल हुए थे।

## बजट में चीन समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद घटाई

पैकेज में 370 करोड़ कम किए, श्रीलंका को अब 4 गुना ज्यादा मदद देगी भारत सरकार

**नई दिल्ली।** मोदी 3.0 सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इसमें विदेश मंत्रालय को 22 हजार 154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह 2023-24 के बजट से करीब 24त्न यानी कम है।

पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29 हजार 121 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें 6,967 हजार करोड़ की कटौती की गई है। विदेश मंत्रालय के बजट में नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई है।

इनमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल हैं। इसके अलावा कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और यूरोएशियाई देशों के लिए भी एड का प्रावधान है। सबसे ज्यादा राशि भूटान को दी गई है। भूटान के लिए 2 हजार 68 करोड़ का पैकेज रखा गया है। हालांकि, यह पिछले साल से करीब 400 करोड़ कम है।

श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी है। वहीं नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ किया गया है।

वहीं अफगानिस्तान, मालदीव और म्यांमार को मिलने वाला पैकेज कम कर दिया गया है। मालदीव को पिछले साल 770 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी, जबकि इस साल इसे घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है।

इसी के साथ भारत सरकार दूसरे देशों की मदद के लिए कुल 4 हजार 773 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

## नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी : सुको

**नई दिल्ली।** नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, मंगलवार को पांचवीं सुनवाई में यह आदेश दिया। सीजेआई ने कहा, पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।

अदालत ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब सुनाएगी, यह नहीं बताया है। नीट

की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है।

सीजेआई ने कहा- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।

## टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी

**नई दिल्ली।** मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज और महंगी होंगी। ये कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। केयरएज रेटिंग्स के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया की प्रति यूजर औसत आय 182 से 15% बढ़कर 220 हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी आरपीयू 300 से ऊपर ले जाने की है। भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है, 'प्रति यूजर आय 300 तक पहुंचने के बाद भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा।

देश में इंटरनेट की पहुंच 2014 में सिर्फ 13.5% थी, जो 2024 में चार गुनी यानी 52.2% हो गई।

## चुनिंदा मामलों में ही जमानत पर रोक लगे : सुको

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के पास बेल ऑर्डर पर स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन यह स्टे सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही लगाना चाहिए। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

दरअसल, खुराना को ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट से जून 2023 में बेल मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि एक साल तक एक शख्स बिना किसी कारण के जेल में सड़ रहा है।

मामले की पिछली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से सवाल किया था कि ट्रायल कोर्ट ने 2023 में बेल ऑर्डर दे दिया था। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इस पर ईडी के वकील ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने सभी फैक्टर को ध्यान में रखकर फैसला नहीं सुनाया था। मामले से कई जजों ने अपने आप को भी अलग कर लिया था। खुराना पर बहुत बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

## भोपाल में प्रदेश भर के सरपंचों का प्रदर्शन

मंत्री से चर्चा में नहीं बनी बात, दो गुटों में बंटे सरपंच

**भोपाल।** राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के 23 हजार पंचायतों से सरपंच मंगलवार को पहुंचे। सरपंच अपनी क मांगों को लेकर को सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद लिंक नंबर दो स्थित सेकेंड स्टाप अंबेडकर मैदान में जमा हुए। मुख्यमंत्री निवास घेरने निकले सरपंच सड़क पर ही बैठ गए। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल उन्हें मनाने पहुंचे थे लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि शाम होते-होते सरपंच दो भागों में बट गए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के धरना स्थल पहुंचने से बीजेपी समर्थक सरपंच वहां से चले गए।

राजधानी पहुंचे सरपंचों का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि सरपंच आज यहां आने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हमारा यहां अपमान हो रहा है। कल से सभी

पंचायतों में तालाबंदी रहेगी।

गौरतलब है सरपंचों के 3 गुटों ने संयुक्त रूप से सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया था। सरपंचों से बात करने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे। लेकिन, सरपंच मंत्री की बात से सहमत नहीं हुए। इसके बाद वे सीएम हाउस घेराव के लिए निकल पड़े। सरपंच जैसे ही आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस के घेरे को तोड़कर महिला सरपंच आगे बढ़ने लगीं तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की अफवाह फैलाई गई है। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। सिर्फ नाम मांगे गए थे। मुख्यमंत्री हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता हम यही सड़क पर बैठेंगे। जितने भी दिन बीत जाए हम मांगे पूरी कराए बिना जाने वाले नहीं है। सरपंचों ने सरकार से 15 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन की मांग की है। सरपंच संघ के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी ने बताया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सरपंचों के धरना स्थल में पहुंचकर पार्टी बाद कर दिया है। इसलिए हम लोगों ने वहां से जाना उचित समझा। केवल कांग्रेसी सरपंच अब प्रदर्शन में बचे हुए हैं। चौधरी ने कहा कि हमारे मंत्री से बात हुई है कुछ मांगों पर सहमति बनी है कुछ मांगों पर अभी बात नहीं हो पाई है। सरपंचों के धरना-प्रदर्शन में सरपंचों का समर्थन करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरपंचों के साथ है। सरपंचों को प्रतिमाह 20 हजार और पंचों को 5 हजार वेतन दिया जाना चाहिए। पटवारी ने कहा कि मप्र की ग्राम पंचायतों का जो स्वरूप है, वह अधिकारियों के भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। संरपंच को उसका अधिकार मिलेगा तो वह गांव का विकास कर सकेगा, जनता का काम करने वाले गांव के प्रतिनिधि को मानदेय मिले, क्योंकि जनता के बीच जबावदेही सरपंच की होती है। मुख्यमंत्री से सवाल करते हुये पटवारी ने कहा कि जनता के भारी समर्थन से आपकी सरकार बनी है, यदि आप अलोकतांत्रिक निर्णय लेंगे तो जिस जनता ने आपको चुना वही जनता आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है।

# कलेक्टर साहब शिक्षकों को किए हैं अटैच, वहीं देंगे जानकारी, डीईओ बोलें मेरे पास नहीं है कोई रिकॉर्ड

## शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का खेल, यहां नहीं चलते कोई नियम-कायदे, पैसे देकर मलाईदार सीटों पर जमे हैं शिक्षक

**सिंगरौली।** प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के नियम-कायदे सिंगरौली जिले में बिल्कुल नहीं चलते हैं। शिक्षा विभाग में दशकों से अटैचमेंट के नाम पर नया खेल बड़ी तेजी से चल रहा है। लोक शिक्षण आयुक्त ने भले ही शिक्षकों के अटैचमेंट को खत्म करते हुए मूल पद स्थापना के कार्य के लिए मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन यहां के जिम्मेदार मनमानी करने पर उतारू है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है। तो वही डीईओ शिक्षकों के अटैचमेंट में गैर जिम्मेदाराना बयान दें रहें हैं।

गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय का स्पष्ट आदेश है कि किसी शिक्षक से गैर शिक्षकीय कार्य नहीं कराया जाए। लोक शिक्षण संचालक शिल्पी गुप्ता ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि अगर शिक्षक किसी दूसरे स्कूल या अन्य विभाग में अटैच हैं तो उन्हें तत्काल उनकी मूल संस्थाओं में भेजा जाए। लेकिन रोक के बावजूद भी दो दर्जन से अधिक लोग अटैचमेंट के नाम पर कलेक्ट्रेट डीईओ कार्यालय, डीपीसी कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय में मलाईदार कुर्सी में जमे हुए हैं। वहीं डीईओ एसबी सिंह से जिले में अन्य विभागों में अटैचमेंट शिक्षकों की जानकारी पूछी गई। जहां उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि कितने शिक्षक अटैच है, मुझे नहीं मालूम। मैंने शिक्षकों को अटैच नहीं किया है। कलेक्टर ने किया है, वही जानकारी दे पाएंगे।

### हर साल अटैचमेंट समाप्त के आदेश

वर्ष में कई बार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी कर अटैचमेंट समाप्त करने की बात कही जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शिक्षकों से कोई भी गैर शिक्षकीय कार्य न कराने के पत्र जारी कर देते हैं। बावजूद इसके शिक्षकों के अटैचमेंट बना रहता है। कभी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तो कभी अपने चहेते अधिकारियों के ऑफिस में अटैचमेंट करा ही लेते हैं। शिक्षक अवैध कमाई करने और आराम के लिए हर एक आदेश को ठेंगा दिखा देते हैं और अपने मनमुताबिक नौकरी बजाते हैं।

### लम्बें समय से चल रहा अटैचमेंट का खेल

जिले में शिक्षकों के अटैचमेंट का खेल कोई नया नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा है। कभी अधिकारी अपने काम की सुविधा के लिए शिक्षकों को अटैच कर लेते हैं तो कभी शिक्षक स्वयं मलाईदार कुर्सी के लिएए स्कूल न जाना पड़ेए इसलिए ले देकर अपना अटैचमेंट अपने घर के पास या किसी कार्यालय में करा लेते हैं। सूत्रों का दावा है कि कलेक्ट्रेट, डीपीसी और डीईओ कार्यालय में अटैचमेंट शिक्षक जमकर अवैध वसूली करते हैं।

## सर्प दंश से पति की मौत, पत्नी गंभीर, पहुंचे क्षेत्रीय विधायक

**सिंगरौली।** देवसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उज्जैनी में बीती रात सर्प ने पति व पत्नी को डस लिया था। इस घटना में पति की मौत हो गई। जहां पत्नी को उपचार के लिए ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया। घटना की खबर जैसे ही क्षेत्रीय विधायक राजेन्द्र मेश्राम को लगी तो मृतक के घर पहुंच ढाढस बंधाते हुये 4 लाख रूपये शासकीय आर्थिक राशि सहायता दिलाने की बात कही। जानकारी में बताया गया कि उज्जैनी निवासी रामसजीवन जायसवाल को घर में ही रात को सर्प ने काट लिया था। जहां उनकी मौत हो गई थी और उनकी पत्नी को गंभीर हालत में ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया। वही वन विभाग की टीम को बुलाकर सर्प को पकड़ने के निर्देश विधायक के द्वारा दिया गया। अभी भी रामसजीवन जायसवाल की पत्नी गंभीर हातल में है।

# सुहिरा पटवारी राजेश नामदेव को हटाने कलेक्टर से शिकायत

## कलेक्टर से कहा पीएम किसान के नाम पर लिया पैसा वापस दिलाए

**सिंगरौली।** जिले भर में राजस्व में जमकर भर्रेशाही चल रही है। पटवारी सीमांकन बटनवारा तरमीम के नाम पर कास्तकारों से जमकर बेजा वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही मामला कलेक्टर के जनसुनवाई में आज दिन मंगलवार को पहुंचा। जहां सुहिरा पटवारी राजेश नामदेव ने पीड़ित से सीमाकंन के नाम पर पैसा लिया। पीड़ित ने कलेक्टर से फरियाद करते हुये पैसा दिलाए जाने की मांग की है। सुहिरा निवासी देवी दयाल शाह तहसील माड़ा ने बताया कि मैं विकलांग हूँ। मेरे दो पुत्र हैं। अभिषेक व नितेश शाह इनके नाम पर सुहिरा में आराजी नम्बर 700/2, 864 के भूमि स्वामी हैं। पीएम किसान योजना के नाम पर पटवारी के द्वारा 10 हजार रूपये लिया गया है। 10 माह पहले पटवारी द्वारा आज दिवस तक काम नही किया। पैसा मागने पर पटवारी द्वारा बोला जाता है कि ज्यादा इधर-उधर करोगे तो तुम्हारी जमीन किसी दूसरे के नाम पर कर दूंगा। इसी बात को लेकर जब पीड़ित जमीन का सीमाकंन कराने के लिए पटवारी के यहां आवेदन किया तो पटवारी के द्वारा जमीन का सीमाकंन नही किया जा रहा है। यह कोई पहला मामला नही है। जिले भर में इसी तरह का खेल खेला जा रहा है। पटवारियों के तानाशाही से किसान कास्तकार परेशान हाल रहते हैं। जब तक उनके मनमुताबिक पैसा नही मिल जाता तब तक उनकी कलम नही चलती है। इसके बावजूद ऐसे पटवारियों पर लगाम कसने में प्रशासनिक अधिकारी क्यो नही दिलचस्पी दिखाते हैं। यह बात हजम नही होती। कार्रवाई न होने के वजह से इनके हौसले बुलन्द बने रहते हैं। पीड़ित ने कलेक्टर से फरियाद करते हुये पैसा दिलाए जाने की मांग की है।

# कलेक्टर ने की 265 आवेदन पत्रों पर जनसुनवाई

**सिंगरौली।** जिले के विभिन्न अंचलो से आयें 265 आवेदको ने जन सुनवाई में कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला को अपना आवेदन देते हुये अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने सभी आवेदन पत्रों पर गंभीरता पूर्वक जन सुनवाई करते हुये कई आवेदको के समस्याओं का जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से निराकरण कराया गया। साथ ऐसे आवेदक जिनके आवेदनों का निराकरण जन सुनवाई के दौरान नही किया जा सका। संबंधित विभागीय अधिकारी की ओर भेजते हुये आवेदन पत्रों का तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर अरविंद झा, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम सृजन बर्मा, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, तहसीलदार रमेश कोल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुराग मोदी, सहायक आयुक्त जन जाति कार्य विभाग, संजय खेडकर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

## समितियों से नगद राशि पर खाद वितरण प्रतिबंधित है : पीके मिश्रा

**सिंगरौली।** उपायुक्त सहकारिता पीके मिश्रा ने बताया की विभागीय निर्देशानुसार वर्तमान खरीफ सीजन में जिले के सभी पैक्स समितियों में किसानों ने धारित भूमि के रकबे के आधार पर साख सीमा तैयार की जाकर परमिट पर कर्ज के रूप में ही खाद का वितरण किया जा रहा है। किसी भी समिति में खाद का नगद वितरण नहीं किया जा रहा है। समितियां से नगद वितरण प्रतिबंधित है। इसलिए समितियां से खाद की कालाबाजारी किए जाने या खाद की अधिक राशि किसानों से लिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

# डीआईपी योजना के अंतर्गत बरगवां में शिविर हुआ सम्पन्न

## दिव्यजनों को कृत्रिम उपकरण किए गए वितरित

**सिंगरौली।** सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने संचालित डीआईपी योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए जनवरी 2024 में आयोजित चिन्हांकन कार्यक्रम तहत नगर पर्षद बरगवां में वितरित किया गया । वितरण कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने आम जनता को चल रहे राजस्व महाअभियान 2.0 का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया । वहीं देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम ने दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग मोदी ने अवगत कराया गया की सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने संचालित डीआईपी योजना अंतर्गत दिव्यांग

जनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए जा रहा है। जिसके तहत 6 चरणों में 421 लाभार्थियों 642 उपकरणों का वितरण कर योजना के तहत लाभान्वित किया गया। इससे अतिरिक्त दिव्यांग जनों के लिए बरगवां में दिव्यांग स्कूल का निर्माण किया गया है। जिसका संचालन अगस्त तक कर लिया जाएगा। इस विद्यालय में 100 मुख बधिर तथा नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित किया जाएगा। इस विद्यालय का लाभ कक्षा 1 से कक्षा पांचवी तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय में 60 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा भी दी जाएगी। विद्यालय में लिफ्ट के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि छात्रों को आवाजाहि में परेशानी ना हो। प्रशासन की योजना अंतर्गत दिव्यांग छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति तथा प्रशासनिक परीक्षाओं में क्वालीफाई करने वाले दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी है।

कलेक्टर ने बताया कि सामाजिक न्याय का अधिकार सभी जनों को है। इसीलिए लोक कल्याण व्यवस्था से संबंधित योजनाओं के ने दिव्यांगों को सम्मान पहुंचाने तथा देश की भागीदारी में सहयोग देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाएं का लाभ जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक दिव्यांगो को दिलाया जायेगा। उन्होंने जनता को प्रशासन ने चलाई जा रही सभी योजनाओं से अवगत करवाया और आम जनता से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। देवसर विधायक ने कहा की प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए सारगर्वित योजनाओं का संचालन जिला प्रशासन द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। प्रशासन के साथ-साथ जनता को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने परिसर को स्वच्छ साफ और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस कर्तव्य का पालन करने से हम फैल रही संक्रमित बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुभाष बर्मा, नगर परिषद बरगवां की अध्यक्ष प्रमिला देवी सहित दिव्यांग जन मौजूद रहे।

# एएसपी ने प्रत्येक फरियादियों की सुनी समस्या

**सिंगरौली।** एएसपी शिव कुमार वर्मा ने एसपी कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान उपनिरीक्षक प्रियंका शर्मा, उपनिरीक्षक शिव कुमार दुबे, महिला थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई शिव कुमार वर्मा एसपी के द्वारा आयोजित की गई। जनसुनवाई में विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किये गये। जिसे प्रत्येक आवेदकों से

रूबरू होकर उनकी शिकायतों को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरता पूर्वक सुना जाकर कई शिकायतो का मौके में निराकरण कराया गया तथा शेष आवेदन पत्र में वैधानिक कार्यवाही हेतु राजपत्रित अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में महिला फरियादियों की शिकायतों को तत्परता से कार्यवाही किये जाने के लिए उपनिरीक्षक प्रियंका शर्मा महिला पुलिस अधिकारी-कर्मचारीयों से शिकायतों की कॉउंसलिंग कराई जाकर उनकी शिकायतो के निराकरण एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया।

## अंतरक्षेत्रीय ब्रिज प्रतियोगिता में एनसीएल ककरी रहा विजेता

**सिंगरौली।** शनिवार को एनसीएल के ककरी क्षेत्र में अंतरक्षेत्रीय ब्रिज प्रतियोगिता 2024-25 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि विभागाध्यक्ष कार्मिक कल्याण राजेश चौधरी मौजूद रहे।

इसी दौरान श्री चौधरी ने अपने उद्बोधन में खेल-कूद को दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए आह्वान किया। उन्होनें कहा कि खेल-कूद से शारीरिक एवं मानसिक सुदृढ़ता आती है।

# सरहंगों ने डगा में गिराई बाउंड्री

**सिंगरौली।** बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत डगा में बीते सोमवार की सुबह तकरीबन 8 बजे सरहंगो ने जबरन बनी बाउंड्रीवाल को गिरा दिया। यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित रामनिधि विश्वकर्मा पिता स्व. अयोध्या

प्रसाद विश्वकर्मा निवासी बरगवां ने पुलिस को दिये आवेदन पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुये आरोप लगाया है कि सुरेश गुप्ता उर्फ छविले गुप्ता बरगवां को बरगवां की जमीन विक्रय किया था। उस जमीन के पीछे की जमीन डगा हल्के में आती है। जिसके चारों तरफ बाउंड्रीवाल मेरे द्वारा बनाई गई है। लेकिन बीते दिवस सुरेश गुप्ता चार आदमियों को लेकर आये जबरन बाउंड्री की दिवार को गिरा दिये। मना करने पर गाली गलौज करते हुये घर में आग लगा देने की धमकी के साथ जान से मारने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि सुरेश गुप्ता करोड़पति है। हम गरीब व्यक्ति हैं। यही वजह है कि हमारे साथ जबरजस्ती कर रहा है। सुनवाई नही हो रही है। पीड़ित ने बरगवां पुलिस को लिखित शिकायत दी है।

# केन्द्रीय बजट भारत की आर्थिक दशा को बदलेगा : मनोरमा

**सिंगरौली।** केंद्रीय बजट 2024-25 वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उक्त बाते सीए मनोरमा शाहवाल ने कही। उन्होंने आगे कहा कि बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य और घरेलू प्राथमिकताओं की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया। यह बजट आर्थिक लचीलापन और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि यह बजट स्थिरता और गतिशीलता के बीच संतुलन पैदा करेगा। बजट में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा की। जिससे ऑटोमोबाइल

विशेष रूप से प्रवेश स्तर के दोपहिया और ट्रैक्टरों की ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार ने कई घोषणाएं की। जिनमें महिलाओं ने खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब डेवलअप करने की परिकल्पना 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाएँ, 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना मुख्य रहा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी)में वृद्धि की घोषणा की। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.0125 प्रतिशत से बढ़कर 0.02 प्रतिशत हो जाएगा। जबकि ऑप्शंस पर एसटीटी 0.0625 प्रतिशत से बढ़कर 0.10 प्रतिशत हो जाएगा।

# अभावि परिषद देवसर की नई कार्यकारिणी गठित

**सिंगरौली।** शासकीय महाविद्यालय देवसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई देवसर की नवीन कार्यकारिणी घोषणा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री अरुणेंद्र पाण्डेय नगर इकाई देवसर के नगर अध्यक्ष डॉ. अरुण पाण्डेय भाग संयोजक अनुराग सिंह प्रांत कार्यकारिणी सदस्य तथा नगर इकाई देवसर नगर मंत्री सौरभ द्विवेदी मौजूद रहे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद तथा विद्या की देवी मां सरस्वती जी का पूजन अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात नगर अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया। विभाग संगठन मंत्री अरुणेंद्र पाण्डेय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यों एवं उद्देश्यों तथा छात्रहित एवं समाज हित में छात्र अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं । इनके द्वारा बताया गया भाग संयोजक अनुराग सिंह द्वारा कार्यकारिणी की घोषणा की गई जिसमें डॉ. अरुण पाण्डेय को पुनः नगर अध्यक्ष का दायित्व मिला तथा अभिनय चतुर्वेदी को नगर मंत्री की जिम्मेदारी मिली जिसमें सभी दायित्मन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही।

# सीएम हेल्पलाइन निराकरण में अर्चना व शिवपूजन हुये सम्मानित

**सिंगरौली।** पुलिस महा निदेशक के आदेश के बाद सिंगरौली पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता व एएसपी शिवकुमार वर्मा के सतत निगरानी में बरगवां व विंध्यनगर थाना सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में सूझबुझ दिखाते हुये सही तरीके से समय अवधि में निराकरण किया है। जहां बीते सोमवार को कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा बरगवां थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा व विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी को सम्मानित करते हुये प्रशस्ति पत्र दिया है। बता दे कि आम जनता को जब शिकायत का निराकरण नही मिलता तो मजबूर होकर सीएम हेल्पलाइन करते हैं। ताकि वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आये और उसका निराक रण समय सीमा में हो सके। दोनों थानों में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुये अधिकारियों ने शत प्रतिशत निराकरण करने की कोशिश की। जनता को लाभ मिला। इसी को देखते हुये सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के मामले में दोनों थाना प्रभारियों को कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मनित किया है।

# पेश बजट विकसित भारत के चार महत्वपूर्ण स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त एवं समृद्ध करने वाला : सांसद

**सीधी।** भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विकसित भारत की दिशा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हू।

सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के चार महत्वपूर्ण स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त एवं समृद्ध करने वाला है। आज पेश हुए बजट में 3 लाख तक की इन्कम पर कोई टैक्स न लगना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और एम यस एम ई के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्गीय को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही 20 लाख तक का नए रोजगार के लिए त्रण देना, ऐसी अनेकों योजनाएं और स्कीम बजट में शामिल की गई है। बजट पेश होने के साक्षी रहे सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में समृद्धशाली और विकसित भारत की झलक दिखती है। इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं इससे छोटे किसानों को सब्ज़ियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।

## बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला : शरदेन्दू तिवारी

भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री और चुरहट के पूर्व विधायक शरदेंदु तिवारी ने कहा कि लगातार सातवीं बार बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने देश को विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बनाया है। अब विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला यह बजट है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया बजट, गरीबी को समाप्त करने और गरीबों का सशक्तिकरण करने में सहयोगी होगा ।3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। गरीब व मध्यम वर्गीय को टैक्स में छूट देकर उनका सशक्तिकरण किया गया है। जिसके कारण मिडिल क्लास का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। कुल मिलाकर पेश हुए बजट में गरीब, किसान और गांव का सशक्तिकरण होगा।

## नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और नए स्टार्टअप लेकर आया है यह बजट : देव कुमार

भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पेश किए गए बजट में देश नई ऊर्जा, युवाओ के लिए नए रोजगार और नए स्टार लेकर आया है। यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनस और इन्टरप्रन्सिप को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है। जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी। आज पेश हुआ बजट विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला बजट साबित होगा। पेश हुए बजट में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके कारण देश में नए इकोनामिक हब बनेंगे।

## सतत एवं समावेशी विकास बजट की प्राथमिकता : रीती पाठक

सीधी विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। इसमें कृषि क्षेत्र पर खास फोकस किया गया है। उसके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आम बजट को अमृत काल के लिहाज से अहम बताया यह जो पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विधायक रीती पाठक ने कहा कि इस बजट में 9 प्राथमिकताएं है, जिसमे खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसलिए यह बजट एक तरफ जहां विकसित भारत के 2047 के सपने को साकार करेगी वहीं दूसरे तरफ देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

# किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा सकते हैं: उप संचालक कृषि

**सीधी।** उप संचालक कृषि ने जानकारी देकर बताया है कि सीधी जिले के किसान 31 जुलाई 2024 तक अपनी खरीफ फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई जिले में एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करा सकते है। ऋणी कृषको का सम्बंधित वित्तीय बैंक (संस्था) के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा। अऋणी कृषक सम्बन्धित बैंक से या वीमा अभिकर्ता (कम्पनी के तहसील प्रतिनिधि) एवं सी. एस. सी. अथवा स्वयं पीएम एफ वी बाय पोर्टल के माध्यम से अपनी फसलों का वीमा करा सकते हैं। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सीधी ने बताया कि खरीफ फसलो का बीमा कराने के लिए भू-अधिकार पुस्तिका या बी 1, आधार कार्ड बैंक पासबुक तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फसल बीमा कराये जाने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना बादल, फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, जल भरावं, भू-स्खलन, सूखा, कीट व्याधियां इत्यादि से फसल नुकसान होने पर किसान भाई फसल वीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा के संबंध में किसान भाई एग्रीकल्चर इश्योरेस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18005707115 पर या किसान कॉल सेन्टर (कृषि रक्षक हेल्पलाइन) 14447 अथवा सीधी जिले में पदस्थ फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने के लिए सीधी जिले हेतु पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित के लिए प्रीमियम राशि 817.20 रूपये प्रति हेक्टेयर, धान अधिचित के लिए 617.10 का प्रतिहेक्टेयर तुअर अरहर के लिए 608.22 रुपये प्रति हेक्टेयर मक्का के लिए 597.12 रुपये प्रति हेक्टेयर, तहसील स्तर पर ज्वार के लिए 478.46 रुपये प्रति हेक्टेयर पर, तिल के लिए 471.94 रुपये, कोदो कुटकी के लिए 316.06 रुपये जिला स्तर की फसल पर उड़द के लिए 434.7 रुपये प्रति हेक्टेयर मुंग के लिए 426.56 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि है जो की बीमित राशि का 2 प्रतिशत है।

# सरस्वती विद्यालय करौंदिया में स्वागत समारोह कार्यक्रम संपन्न

**सीधी।** शिक्षा के साथ संस्कारों की जननी सरस्वती विद्यालय करौंदिया में नव निर्वाचित सांसद एवं विद्यालय के पूर्व संरक्षक डॉ.राजेश मिश्रा के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यालय के नाम को प्रदेश स्तर तक पहुँचाने में विशेष योगदान देने वाले विद्यालय के प्राचार्य रमेश चन्द्र त्रिपाठी को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सरस्वती विद्यालय करौंदिया के संस्था अधीक्षक आचार्य राजेश मिश्रा ने बताया कि विगत दिवस आयोजित समारोह में नव निर्वाचित सांसद डॉ.राजेश मिश्रा का विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया वहीं विद्यालय के नवीन प्राचार्य श्रीमती सपना पाण्डेय द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उन्हे भी शुभ कामनायें प्रेषित की गयीं। वहीं कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के पूर्व प्राचार्य रमेश चन्द्र त्रिपाठी को भावभीनी विदाई दी गयी। कार्यक्रम को सम्बोंधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ.राजेश मिश्रा ने कहा कि सीमित संसाधन में विद्यालय के गौरव को बढ़ाने में पूर्व प्राचार्य रमेश चन्द्र त्रिपाठी द्वारा कोई कोर कसर नही छोड़ी गयी। श्री त्रिपाठी जब मड़रिया विद्यालय में सेवायें दे रहें थें तब से लेकर आज दिनांक तक अपने कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में कभी भी शिकायत का मौंका नही दियें। श्री त्रिपाठी बड़े ही कर्मठ योग्य एंव जुझारू व्यक्ति हैं, मैं श्री त्रिपाठी को चुरहट विद्यालय के प्राचार्य पद ग्रहण करने पर शुभ कामनायें प्रेषित करता हूँ। सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरस्वती विद्यालय में पढ़े बच्चे आज बड़े पदो पर आशीन होकर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं। वहीं विद्यालय परिवार द्वारा वर्तमान में आर्थिक स्थिती के चलते विद्यालय का विकास अवरूद्ध होने की बात कही गयी जिस पर सांसद ने कहा कि जल्द ही जन सहयोग से आर्थिक मद्द की जायेगी।

# अपर कलेक्टर ने सुनी 261 आवेदकों की समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश

## वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और सीईओ जनपद

**सीधी**

जिला पंचायत सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 261 आवेदकों की समस्याओं को अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही ने ध्यानपूर्वक सुना और निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे। अपर कलेक्टर श्री शाही द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए।

अपर कलेक्टर श्री शाही ने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। अपर कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाय। मैदानी स्तर पर सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ सहज रूप से दिलाया जाना सुनिश्चित हो। अपर कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि लोगों की सामान्य समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत, तहसील और नगरीय निकाय के स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, उन्हें अपनी छोटी -छोटी एवं जायज कार्यों के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

जनसुनवाई में वार्ड नं. 04 नूतन कॉलोनी सीधी से आये 61 वर्षीय दिव्यांग गोलाई भुजवा जो ठेला में पूड़ी सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे लेकिन 08 माह पहले लकवा की समस्या हो जाने के कारण पैर सही से काम नहीं कर पा रहा है जिससे चलने बैठने में असक्षम हैं। कहीं भी आने-जाने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर अपर कलेक्टर द्वारा ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। गोलाई को ट्राई सायकिल प्राप्त होने से बहुत सुविधा मिल गयी है। दैनिक क्रियाकलाप में काफी सहूलित हो जाएगी।

इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

# भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा गुरू पूर्णिमा पर प्रतियोगिता आयोजित

**सीधी।** मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी किए गए त्रैमासिक कैलेंडर के अनुसार 21 जुलाई 2024 को गुरू पूर्णिमा के पावन पर्व पर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ में गुरू शिष्य परंपरा पर भाषण प्रतियोगिता तथा गुरू शिष्य परंपरा पर आधारित गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पी.के. सिंह ने किया तथा अपने उद्बोधन में छात्र-छात्राओं को गुरूजनों का सम्मान करने तथा गुरू शिष्य परंपरा का पालन करने के लिए संदेश दिया। डॉ. प्रभाकर सिंह नियंत्रक स्वशासी परीक्षा ने छात्र-छात्राओं को भारतीय परंपरा से जुड़कर और अनुशासन में रहकर विद्या अध्ययन करने का संदेश दिया। डॉ. अनिल कुमार सिंह ने गुरू शिष्य के संबंधों को रेखांकित किया। डॉ. संतोष सिंह विभागाध्यक्ष इतिहास ने वैदिक काल से लेकर अब तक के गुरू शिष्य के संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया। भाषण एवं गीत प्रतियोगिता का संचालन डॉ. आर.एन. स्वर्णकार नोडल अधिकारी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ ने किया। भाषण प्रतियोगिता में कुल 10 छात्र-छात्रओं ने भाग लिया जिसमें प्रथम स्थान अंकुश सिंह परिहार बीए तृतीय वर्ष, द्वितीय स्थान दो छात्र-छात्राओं गौरव त्रिपाठी बीएसी द्वितीय वर्ष एवं अनामिका तिवारी बीए तृतीय वर्ष ने अर्जित किया तथा तृतीय स्थान सत्यजीत गुप्ता बीए फोर्थ ईयर ने अर्जित किया। गीत प्रतियोगिता में पॉच छात्र-छात्राओं ने भाग लिया जिसमें प्रथम स्थान रेशू सिंह एमए द्वितीय सेमेस्टर इतिहास, द्वितीय स्थान काजल शर्मा बीएसी प्रथम वर्ष तथा तृतीय स्थान कृतिका सिंह बीए द्वितीय वर्ष ने अर्जित किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। डॉ. अनिल सिंह प्राध्यापक अंग्रेजी ने छात्र-छात्राओं को अपनी पुस्तकें भेंट की। डॉ. दिवाकर सिंह, डॉ. रविन्द्रनाथ सिंह तथा डॉ. राजेश कुमार विश्वकर्मा प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में रहे।

कार्यक्रम के अंत में नोडल अधिकारी डॉ. आर.एन. स्वर्णकार सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। गुरू पूर्णिमा के इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉ. संतोष सिंह, डॉ. गुलशेर अहमद, डॉ. उमाकांत साहू, डॉ. यज्ञप्रताप साहू, श्री प्रद्युम सोनी, डॉ. दिवाकर सिंह, अरशद अयूब अंसारी, मनोज कुमार प्रजापति की गरिमामयी उपस्थित एवं भूमिका सराहनीय रही।

# सपा प्रदेश अध्यक्ष का सीधी में भव्य स्वागत

**सीधी।** समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज यादव का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ियों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे में स्थापित भारत रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एकर्ताओं से मिलकर पार्टी को बूथ स्तर पर ले जाने एवं संगठन के प्रत्येक जिम्मेदारियां को निर्वहन करके संगठन को मजबूत बनाना है प्रदेश महासचिव राम प्रताप सिंह यादव ने सीधी के जन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को याद दिलाए हैं कि किसान आवारा पशुओं से परेशान है आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है भाजपा सरकार घोटाले की सरकार है बेरोजगार नौजवानों से फार्म भरवा कर पेपर लीक हो जाता है महंगाई भ्रष्टाचार चरण सीमा पर है सीधी जिले में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कई बार विज्ञापन पत्र दिया गया लेकिन कोई अभी तक कार्यवाही नहीं की गई ना तो अभी तक सीधी जिले में लॉ कॉलेज स्थापित हुई आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है पत्रकारों मीडिया बांधों को निष्पक्ष पत्रकारिता करने नहीं दिया जाता उन्हें धमकाया जाता है और कई अन्य जन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को आगाह किए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज यादव पहुंचे सीधी जहां पर बीथिका भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राजेंद्र यादव प्रमुख महासचिव, आर.एन. पटेल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, यश भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरगोविंद चौकसे उपाध्यक्ष, राम प्रताप यादव महासचिव, रामराज यादव, श्रवण कुमार विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह बघेल, एम.डी. खान प्रदेश सचिव सीधी प्रभारी, अशोक यादव रीवा, राकेश यादव, युवजन सभा प्रदेश सचिव राजेंद्र पटेल चुरहट मंच का संचालन कर रहे हैं समर बहादुर एवं मंच के सामने बैठे पदाधिकारी दिनेश यादव जिला महासचिव पूर्व चंद्रभान यादव राजेंद्र यादव एडवोकेट राजरखन यादव राजेंद्र सिंह मृगेंद्र यादव संतोष साकेत, पीएल सोनी, सुरेश यादव राजेश साकेत बैजनाथ साकेत, चित्रसेन यादव, लालू यादव, संत लाल, कृष्ण यादव राव अंबेडकर मनोज यादव सिहावल विधानसभा मनोज रजक जानकी यादव सुग्रीव यादव यज्ञवन गिरी राज बहोरन सिंह सोनवानी सौरव सिंह बाबुल सिंह शुभम सिंह यादव कई प्रदेश पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे एवं प्रदेश अध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम के नाम एसडीम नीलेश शर्मा को ज्ञापन पत्र मांगों को लेकर 10 बिन्दु का ज्ञापन पत्र सौंपा गया।

## केंद्र सरकार के बजट ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेरा

# कृषि उपकरण पर जीएसटी और खाद के दाम कम नहीं हुए : अजय सिंह

**एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी नहीं मिली**

**सीधी**

विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने कहा है कि बजट में देश की बेरोजगारी खत्म करने,महंगाई से राहत दिलाने और किसानों को राहत देने के लिए कोई इच्छा शक्ति और दूर दृष्टि दिखाई नहीं देती है।

अजयसिंह ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने के प्रावधान है और न ही मुफ्त बिजली और सस्ते खाद बीज देने की बात है। सरकार को किसानों के हित में कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाना चाहिए था लेकिन वित्त मंत्री ने नाउम्मीद किया है। किसान कल्याण निधि में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ,शिक्षा, किसान और युवाओं के लिए कुछ नही है। युवा अपने लिए लगातार पक्की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। उसे हमेशा की तरह बहलाया जा रहा है।

**पश्चिम मध्य रेल**

**खुली निविदा (सिंगल पैकेट प्रणाली)**

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-1, पश्चिम मध्य रेल, रीवा, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा नोटिस क्रमांक डिप्टी सी.ई.सी-1-रीवा-8/2024, दिनांक 17.07.2024 के द्वारा आमंत्रित करते हैं। निविदाएं बन्द होने की तारीख 19.08.2024 एवं समय 15:00 बजे तक है। निविदाकर्ता अपनी मूल/ संशोधित निविदा बंद होने के दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त निविदा में हस्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी तथा हस्त निविदाओं को उपेक्षित कर दिया जाएगा। निविदाएं पूर्व उल्लेखित समय एवं दिनांक पर खोली जाएगी। **निविदा क्रमांक:** डिप्टी. सी.ई.सी-1/रीवा-08-2024, दिनांक: 17/07/2024. **कार्य का नाम लोकेशन सहित:** रीवा-सीधी नई बीजी रेल लाइन परियोजना के संबंध में सीएच-87050 पर रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) और सीधी स्टेशन यार्ड में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण। **निविदा का अनुमानित मूल्य:** ₹ 124028029.60/- **निविदा फॉर्म की:** ₹ 0.00 **बयाना राशि:** ₹770200/- **कार्य समापन अवधि (माह):** 06 माह मानसून सहित **ई-निविदा बंद होने की और खुलने की तिथि एवं समय:** दिनांक 19.08.2024 को 15.00 बजे बंद एवं 15.00 बजे के बाद खोली जाएगी। निविदाकर्ता अपनी निविदाएं आई. आर. ई. पी. एस. के माध्यम से https://www.ireps.gov.in पर ऑनलाइन निविदा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है, कि वे समय-समय पर बदलाव व शुद्धि पत्रों हेतु IREPS की वेबसाइट https://www.ireps.gov.in देखते रहें। न्यूनतम पात्रता मानदंड टेन्डर फॉर्म के अनुसार इन निविदाओं के लिए लागू होगा।

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), प.म.रे., रीवा

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

**कार्यालय नगर परिषद मनगवां जिला- रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक/507/ई-निविदा/न.प./2024 मनगवां, दिनांक 19.07.2024

चतुर्थ निविदा (सेक्सन-1)
ई निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद मनगवां द्वारा निम्नानुसार निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्ते एवं जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर Urban administration Development Department से एवं कार्यालय नगर परिषद मनगवां से प्राप्त की जा सकती है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है।

| क्र. | टेण्डर क्र. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख में) | अमानत राशि | निविदा फार्म का मूल्य | कार्य की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024_UAD_258772_1 | वार्ड क्रमांक 08 में विजय मैत्रेय के घर तक आरसीसी रोड का निर्माण कार्य। | 171502.00 | 3430.00 | 2000.00 | 03 माह |
| 2. | 2024_UAD_258772_2 | वार्ड क्रमांक 08 में केदार साकेत के घर से हसन पानवाला तक पीसीसी रोड निर्माण कार्य। | 171502.00 | 3430.00 | 2000.00 | 03 माह |
| 3. | 2024_UAD_258772_3 | वार्ड क्रमांक 08 में जावेद के घर से सूर्यलाल बंधल के घर तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य। | 294469.00 | 2945.00 | 2000.00 | 03 माह |

उक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र उपरोक्तानुसार दिये गये दिनांक 22.07.2024 सुबह 10:30 से दिनांक 22.08.2024 तक सायं 05:30 तक वेबसाईट पर लागू प्रोसेसिंग शुल्क के ऑन लाईन भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगे।

(श्रीमती बुटला बंसल)
अध्यक्ष
नगर परिषद मनगवां,
जिला-रीवा (म.प्र.)

(सुरेश कुमार सोनवानी)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मनगवां,
जिला-रीवा (म.प्र.)

**कार्यालय नगर परिषद मनगवां जिला- रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक/503/ई-निविदा/न.प./2024 मनगवां, दिनांक 19.07.2024

द्वितीय निविदा (सेक्सन-1)
ई निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद मनगवां द्वारा निम्नानुसार निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्ते एवं जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर Urban administration Development Department से एवं कार्यालय नगर परिषद मनगवां से प्राप्त की जा सकती है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है।

| क्र. | टेण्डर क्र. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख में) | अमानत राशि | निविदा फार्म का मूल्य | कार्य की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024_UAD_358770_1 | वार्ड क्रमांक 08 में दिनेश शर्मा के घर से बसोर बस्ती में आरसीसी रोड निर्माण का कार्य। | 678915.00 | 6789.00 | 2000.00 | 03 माह |

उक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र उपरोक्तानुसार दिये गये दिनांक 22.07.2024 सुबह 10:30 से दिनांक 22.08.2024 तक सायं 05:30 तक वेबसाईट पर लागू प्रोसेसिंग शुल्क के ऑन लाईन भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगे।

(श्रीमती बुटला बंसल)
अध्यक्ष
नगर परिषद मनगवां,
जिला-रीवा (म.प्र.)

(सुरेश कुमार सोनवानी)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मनगवां,
जिला-रीवा (म.प्र.)

## संपादकीय

### पहचान का प्रश्न

कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसे उत्तर प्रदेश के एक जिला प्रशासन का स्थानीय स्तर पर लिया गया फैसला माना जा रहा था, वह तेज होते विरोध के बीच न केवल पूरे राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लागू कर दिया गया था। इस आदेश के मुताबिक, कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर दुकान लगाने वाले तमाम लोगों के लिए अपनी पहचान सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस आदेश को लेकर किस तरह का असमंजस फैला है, इसका अंदाजा भाजपा के ही एक प्रमुख नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया से मिलता है। शुरू में इस आदेश के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा, 'कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश... छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं।' विरोध करने वालों में नकवी अकेले नहीं थे। विपक्षी दलों के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से भी इसके विरोध की आवाज उठी थी। माना जा रहा था कि विरोध के बाद जिला स्तर पर हुए इस फैसले को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन कुछ घंटों के अंदर पूरे राज्य में इस आदेश को लागू करने का निर्णय घोषित हो गया। इसके बाद नकवी भी अपना रुख पलटते दिखे। उनका कहना था कि शुरू में उस फैसले ने कुछ कन्फ्यूजन फैलाया था, लेकिन अब सरकार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है।

# आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मीडिया के उलझे रिश्ते

**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को फिर से परिभाषित करने, मानवीय क्षमता की सीमाओं को पार करने और अभूतपूर्व पैमाने पर उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने के लिए तैयार है। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में, एआई का आगमन कंटेंट क्रिएटर्स को सामग्री निर्माण के लिए शक्तिशाली उपकरणों से सशक्त बना रहा है, नए अनुभवों को अनलॉक कर रहा है और कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का उपभोग करने, बनाने और उनसे जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है।**

(प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी)

हाल के कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और पत्रकारिता का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह रहा है। मौजूदा समय में भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा विज्ञापन पर निर्भर होकर काम कर रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन दी जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूं कि तब आपसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये शब्द हैं भारत की पहली एआई बॉट एंकर सना के। आर्टिफिशनल इंटेलिजेंस के मीडिया जगत में बढ़ते इस्तेमाल की कई संभावनाएं हैं। इसी में से एक है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री एक एआई एंकर से देश के भविष्य और योजनाओं के बारे में चर्चा करते दिखें।

दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्स्ट टू स्पीच% फीचर की बदौलत अब भारतीय न्यूजरूम में मशीन को इंसानी चेहरे में ढालकर खबरें पेश की जा रही हैं। पिछले साल अप्रैल के महीने में इंडिया टुडे ग्रुप ने एआई एंकर से समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया था। लॉन्च कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एंकर का परिचय देते हुए कहा गया था कि वह ब्राइट है, सुंदर है, उम्र का उन पर कोई असर नहीं होता है और न ही कोई थकान होती है, वो बहुत सारी भाषाओं में बात कर सकती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को फिर से परिभाषित करने, मानवीय क्षमता की सीमाओं को पार करने और अभूतपूर्व पैमाने पर उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने के लिए तैयार है। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में, एआई का आगमन कंटेंट क्रिएटर्स को सामग्री निर्माण के लिए शक्तिशाली उपकरणों से सशक्त बना रहा है, नए अनुभवों को अनलॉक कर रहा है और कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का उपभोग करने, बनाने और उनसे जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है।

हाल के कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और पत्रकारिता का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह रहा है। मौजूदा समय में भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा विज्ञापन पर निर्भर होकर काम कर रहा है। ऐसे में तकनीक के जरिये डेटा के आधार पर समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करना और अन्य काम भी इंसान की जगह मशीन की बदौलत होने ने मीडिया इंडस्ट्री के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारिता के भविष्य से लेकर पत्रकारिता करने वालों के भविष्य को लेकर भी संकट खड़ा होने की बात कही जा रही है। लेकिन एआई पत्रकारिता वास्तव में क्या है? क्या यह चिंता का एक विषय है या फिर सूचना जगत में एक ऐसी नई क्रांति है, जो पत्रकारिता के सही आयाम स्थापित करने में कामयाब हो पाएगी।

**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पत्रकारिता:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के लगभग सभी पहलूओं समेत पत्रकारिता में भी शामिल हो गई है। डिजिटल मीडिया की वजह से जाने-अनजाने में ही एआई तकनीक पर आधारित कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वह यू-ट्यूब के एल्गोदिरम की वजह से आपको दिखते वीडियो हों या वेबसाइट पर दिखने वाले विज्ञापन। सभी का एक कारण एआई तकनीक ही है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से एआई पत्रकारिता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मीडिया कंपनियां अपने कंटेंट को अधिक बूस्ट करने के लिए एआई की मदद ले रही हैं। लेख लिखने से लेकर बुलेटिन प्रसारित करने तक में एआई का सहारा लिया जा रहा है। दुनिया भर के बड़े-बड़े मीडिया हाउस एआई द्वारा लिखे लेख को प्रकाशित कर रहे हैं। एक तरफ तो यह काम को आसान और तेजी से कर रहा है, दूसरी ओर यह कई सवाल भी खड़े करता है जिसमें विश्वसनीयता और अखंडता सबसे पहले है। साथ ही क्या सजृनशीलता पर आधारित क्षेत्र में एआई से डेटा आधारित बातचीत और जानकारी, पत्रकारिता के धरातल पर काम कर पाएगी? पत्रकारिता के सबसे मजबूत और शुरुआती मूल्य ग्राउंड रिपोर्टिंग का भविष्य इससे बच पाएगा?

**खतरे में पत्रकारों की नौकरियां:** इंसान की जगह मशीन के इस्तेमाल होने का पहला खतरा इंसानों पर ही पड़ता है। न्यूज़जीपीटी, दुनिया का पहला समाचार चैनल है, जिसका पूरा कंटेंट आर्टिफिशल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया जा रहा है। चैनल के प्रमुख एलन लैवी ने इसे खबरों की दुनिया का गेम चेंजर कहा था, क्योंकि ना इसमें कोई रिपोर्टर है और ना ही यह किसी से प्रभावित है। यहां यही बात मीडिया जगत में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा है। जैसे-जैसे मीडिया के क्षेत्र में एआई का प्रभुत्व बढ़ रहा है, वहां मौजूदा लोगों की नौकरियों पर तकनीक का कब्जा होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। लेखन, संपादन, एंकरिंग, प्रस्तुतीकरण तक के सारे कामों में एआई का सहारा लिया जा रहा है।

बीबीसी द्वारा प्रकाशित एक समाचार के अनुसार साल 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी संख्या मे %एमएसएन% वेबसाइट के लिए लेखों के चयन, क्यूरेटिंग, हेडलाइन तय करने और एडिटिंग करने वाले पत्रकारों की जगह स्वचलित सिस्टम को अपनाने की योजना बनाई। खबर के अनुसार कंपनी ने एआई तकनीक के सहारे खबरों के प्रोडक्शन के कामों को पूरा करना तय किया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी अन्य टेक कंपनियां मीडिया संस्थानों को उनका कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करती हैं। इन सब कामों के लिए पेशेवर पत्रकारों की मदद ली जाती आई है, जो कहानियां तय करने, उनका प्रकाशन कैसे होना है, हेडलाइन तय करने जैसे काम करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के एआई तकनीक के इस्तेमाल के बाद से लगभग 50 न्यूज प्रोड्यूसर्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।

ठीक इसी तरह साल 2022 के अंत में अमेरिकी टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट सीएनईटी एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चीजें अलग ही स्तर पर ले गई। कंपनी ने एआई प्रोग्राम के तहत लिखे गए दर्जनों फीचर लेख चुपचाप तरीके से प्रकाशित किए। जनवरी 2023 तक कंपनी ने इन सब अटकलों की पुष्टि नहीं की थी, जिसे केवल एक प्रयोग बताया जा रहा था। इतना ही नहीं एसोसिएटेड प्रेस ने भी अपनी कहानियों के लिए एआई का इस्तेमाल किया। ये सब बातें बताती हैं कि कैसे समाचारों को चुनने, उनको व्यवस्थित करने के लिए काम करने वाले मीडिया के पेशेवरों की नौकरियां एआई ले रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन अभी से न्यूजरूम के भीतर उसकी मौजूदगी से मीडिया पेशवरों की नौकरियों पर संकट बनना शुरू हो चुका है। डायच वेले के अनुसार हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े पब्लिकेशन हाउस %एक्सल स्प्रिंगर% ने कई संपादकीय नौकरियों को एआई में बदल दिया है। स्प्रिंगर में नौकरियों की कटौती से मीडिया उद्योग के रोबोट पर निर्भरता की आशंकाओं में तेजी ला दी है। भारत समेत कई अन?य देशों में न्यूज एंकर के तौर पर कम्प्यूटर जनित मॉडल यानी एआई एंकर समाचार पढ़ते नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक इंसानी तौर पर दिखने वाले ये न्यूज एंकर कॉर्पोरेट मीडिया हाउस के मुनाफे वाले दृष्टिकोण से हितैषी हैं, क्योंकि इन्हें न कोई सैलरी की आवश्यकता है, ना छुट्टी की। ये 24 घंटे और सातों दिन डेटा के आधार पर काम कर सकते हैं। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर सना के लॉन्च के समय इसी तरह के शब्द कहे गए थे कि वह बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती है।

# महानगरों में बढ़ता जानलेवा प्रदूषण गंभीर चुनौती

**भारत के दस बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में सात फीसदी से अधिक का मुख्य कारण हवा में व्याप्त प्रदूषण है। वहीं दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण के रूप में पसर रही मौत के लिये सरकार एवं उनसे संबंधित एजेंसियों की लापरवाही एवं कोताही शर्मनाक है, क्योंकि सरकार द्वारा 131 शहरों को आवंटित धनराशि का महज 60 फीसदी ही खर्च किया जाता है। गंभीर से गंभीरतर होती वायु प्रदूषण की स्थितियों के बावजूद समस्या के समाधान में कोताही चिन्ता में डाल रही है एवं आम जनजीवन के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। महानगरों में प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी।**

(ललित गर्ग )

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके।

चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी चर्चित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लासेंट के हाल के अध्ययन में वायु प्रदूषण की बढ़ती विनाशकारी स्थितियों के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले है बल्कि अत्यंत चिन्तातनक है। भारत के दस बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में सात फीसदी से अधिक का मुख्य कारण हवा में व्याप्त प्रदूषण है। वहीं दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण के रूप में पसर रही मौत के लिये सरकार एवं उनसे संबंधित एजेंसियों की लापरवाही एवं कोताही शर्मनाक है, क्योंकि सरकार द्वारा 131 शहरों को आवंटित धनराशि का महज 60 फीसदी ही खर्च किया जाता है। गंभीर से गंभीरतर होती वायु प्रदूषण की स्थितियों के बावजूद समस्या के समाधान में कोताही चिन्ता में डाल रही है एवं आम जनजीवन के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। महानगरों में प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार की कोशिश थी कि देश के चुनिंदा एक सौ तीस शहरों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2024 तक घातक धूल कणों की उपस्थिति को बीस से तीस फीसदी कम किया जा सके। लेकिन विडम्बना है कि तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। महानगरों-नगरों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हालांकि लोगों को सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है, एंटीडस्ट अभियान को निरन्तर जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को खुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को खुली जगह में कूड़ा नहीं फैंकना चाहिए और न ही उसे जलाया जाए। वाहनों का प्रदूषण लेवल चैक करना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली पटाखे जलाने की भौतिकतावादी मानसिकता को विराम देना जरूरी है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अभिधारणा को मूर्त रूप देने के लिये इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की दिशा में गत दो-तीन साल में कई पायदान हम ऊपर चढ़े हैं, एक सकारात्मक वातावरण बना। लेकिन पटाखों से ज्यादा खतरनाक हैं पराली का प्रदूषण। पराली आज एक राजनीतिक प्रदूषण बन चुका है। दिल्ली एवं पंजाब में एक ही दल ही सरकारें है, दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार समाधान देती।

प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता। इसके लिये शहरों में वृक्षारोपण करके हरियाली का दायरा बढ़ाना, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, इलेक्ट्रानिक वाहनों को प्रोत्साहन तथा इन वाहनों के लिये चार्जिंग स्टेशन बनाने जैसे प्रयास करने के सुझावों का क्रियान्वित करने की अपेक्षा है, इसके लिये जो कार्यक्रम प्रदूषण से ग्रस्त चुनिंदा शहरों में चलाया जाना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जिससे समस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही है। इसी कारण देश के अधिकांश शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। लेकिन स्थानीय निकायों व प्रशासन ने संकट की गंभीरता को नहीं समझा। इस दिशा में अपेक्षित सक्रियता नजर नहीं आई। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे महानगरों को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? सरकारें एवं राजनेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठहराने की बजाय समाधान के लिये तत्पर क्यों नहीं होते? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही है?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये सक्रिय है, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये करीब साढ़े दस हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। लेकिन विडम्बना है कि पर्याप्त फण्ड होने के बावजूद सिर्फ साठ फीसदी राशि ही इस मकसद के लिये खर्च की गई। वहीं सत्ताईस शहरों ने बजट का तीस फीसदी ही खर्च किया। कुछ शहरों ने तो इस मकसद के लिये आवंटित धन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। कैसे समस्या से मुक्ति मिलेगी? जीवाश्म ईंधन के उपयोग, सड़कों पर निरंतर बढ़ते पेट्रोल-डीजल वाहन, सार्वजनिक यातायात की बदहाली व कचरे का ठीक से निस्तारण न होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लक्ष्य हासिल करना जटिल होता जा रहा है। अब समस्या की विकरालता को देखते हुए केंद्र सरकार इस दिशा में नये सिरे से गंभीरता से पहल कर रही है, जिससे प्रदूषित शहरों को दी जाने वाली राशि का यथा समय अधिकतम उपयोग हो सके। पराली की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1347 करोड़ रुपये और उपकरण दिए गए। अगर इस पर राजनीति करने की जगह ईमानदारी से काम होता तो प्रदूषण को कम करने की दिशा में हम कुछ कदम बढ़े होते।

## वर्ग पहेली 5440

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | ■ | 3 | | 4 | 5 |
| | ■ | 6 | | | ■ | 7 | |
| 8 | 9 | | ■ | 10 | 11 | ■ | |
| 12 | | ■ | 13 | ■ | 14 | 15 | |
| 16 | | | | ■ | 17 | | ■ |
| ■ | ■ | ■ | 18 | 19 | ■ | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | ■ | 24 | 25 | | ■ |
| 26 | | | ■ | 27 | | | ■ |

**संकेत: बाएं से दाएं**

1. 7 सितंबर 1923 को यहां इंटरपोल की स्थापना हुई (3)
3. यह देश पहले फारमूसा कहलाता था जिसकी राजधानी ताइपे है (4)
6. उत्तराखंड या उत्तरप्रदेश में बहने वाली एक नदी जिसे महाकाली नदी या कालीगंगा के नाम से भी जाना जाता है (3)
7. हाथ, हस्त, महसूल (2)
8. कीडों द्वारा निर्मित एकमात्र पदार्थ जो इंसानों द्वारा खाया जाता है (3)
10. एक बार सांस लेने का समय, बल, शक्ति (2)
12. यह संसार की सबसे लंबी नदी है (लंबाई 6650 कि.मी. चौड़ाई 16 कि.मी.)(2)
14. पुनरागत, लौटा हुआ (3)
16. कूटयुक्तिकर्ता, जुगतबाज (4)
17. खुदकाश्त कृषि, घरजोत (2)
18. मटमैले रंग का प्रसिद्ध धातु (2)
20. पत्नी, लक्ष्मी, सरस्वती, स्त्री (2)
21. भगवान विष्णु का पांचवा अवतार (3)
24. भार माप, महत्व (3)
26. भिक्षा झोली, आंचल (2)
27. मुर्गे आदि पक्षी के सिर पर परों का गुच्छा (3)

**संकेत: ऊपर से नीचे**

1. विदेश के लिए बनाई आचार व्यवहार संबंधी नीति (5)
2. जो खुश न हो, अप्रसन्न, खिन्न (3)
3. कुल संख्या, गणना, गिनती, हिसाब (3)
4. वाक्य का अपभ्रंश वाणी (3)
5. एक प्रकार का फूल (4)
9. कंठ, गले की नली (3)
11. गढपति, किलेदार (3)
13. शिष्टता, विवेक, तहजीब, सभ्यता (3)
15. आज्ञा, अनुमति इजाजत,अध्यादेश (5)
19. स्तुति करने वाले को यह भी कहते है (3)
21. वचन, इकरार, प्रतिज्ञा (2)
22. मेरा या मेरी (संस्कृत)(2)
23. महिला ईसाई पादरी (2)
25. पंच तत्वों में एक, आब, नीर (2)

### वर्ग पहेली 5439 का हल

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पे | इ | चिं | ग | ■ | सु | ल | ह |
| रा | त | ■ | या | मि | नी | ■ | स |
| ई | रा | न | ■ | ल | ल | का | र |
| ■ | ना | ज | नी | न | ■ | म | त |
| मे | ■ | फ | र | सा | ■ | ना | ज |
| घ | न | ■ | द | र | मा | ■ | य |
| दू | भ | र | ■ | ■ | ■ | रि | पु |
| त | ■ | वि | श्व | ■ | सं | त | री |

# सावन के महीने में भगवान शिव के 5 लोकप्रिय मंदिरों के करें दर्शन, पूर्ण होगी हर मनोकामना

(दिव्यांशी भदौरिया )

सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो चुकी है। ऐसे में आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करें। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ काफी देखने को मिल सकती हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के लोकप्रिय मंदिर जहां आप दर्शन के लिए जा सकते हैं।

श्रावण माह की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव का प्रिय माह सावन है। सावन के पवित्र महीने में शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। सावन सोमवार के दिन भक्त सभी उपवास रखते हैं और भोलेनाथ बाबा के दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं। इस दौरान देश के कुछ लोकप्रिय मंदिरों में लाखों की संख्या में भक्त लोग पहुंच जाते हैं। माना जाता है इन मंदिरों में दर्शन करने से जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं देश के लोकप्रिय शिव मंदिरों के बारे में-

### सोमनाथ मंदिर, गुजरात

12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। हिंदू धर्म में यह मंदिर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इस समय, सोमनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु सोमवार को दर्शन करने के लिए दूर-दूर से आते हैं।

### महाकालेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश

दरअसल, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। सावन के समय में यहां लाखों श्रृद्धालुओं की भीड़ उमड़ आती है। भक्त लोग भगवान शिव पर जल चढ़ाने और दर्शन के लिए आते हैं।

### बाबा धाम मंदिर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में बाबा धाम मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बता दें कि, बाबा धाम मंदिर को पूर्वांचल का काशी भी कहा जाता है। सावन के महीने में बाबा धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है।

### त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र

भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह सातवां मंदिर है और शिव जी को समर्पित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। सावन के दौरान यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।

### वाघेश्वर मंदिर, गुजरात

भगवान शिव का यह मंदिर गुजरात के बड़ौदा शहर में स्थित है। वाघेश्वर मंदिर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। सावन के दौरान, वाघेश्वर मंदिर में काफी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है।

## आज का राशिफल

### मेष

आज संतान के करियर को लेकर जो परेशानियां बनी हुई थीं, वे दूर हो जाएंगी। आपको अपने प्रियजनों और परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप किसी नए कारोबार के बारे में सोच सकते हैं लेकिन नौकरी के मामले में संघर्ष बढ़ेगा।

### वृषभ

आज आपके प्रियजनों और रिश्तेदारों में किसी को शारीरिक कष्ट होने की सूचना दे रहा है। फिजूल खर्ची और विवाद से दूर रहें। सायंकाल से लेकर देर रात्रि तक पारिवारिक जनों के साथ यात्रा का सुख प्राप्त होगा। शुभ व्यय से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। नौकरी के बड़े अवसर मिल सकते हैं।

### तुला

आज अकस्मात् बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ होने का योग बना रहेगा। आपको प्रियजनों का वांछित सुख एवं सहयोग मिलेगा। सायंकाल से लेकर रात्रि तक मंगल कार्यों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मंगल कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। साथ ही करियर में कुछ बदलाव के आसार दिख रहे हैं।

### वृश्चिक

आज संतान पक्ष की चिन्ता रहेगी। संतान को शारीरिक कष्ट होने से आप परेशान रहेंगे। नौकरी से जुड़ा स्थान परिवर्तन होने का प्रसंग प्रबल होकर स्थापित होगा। आर्थिक लाभ तो होगा परन्तु लाभ से अधिक खर्चा होने के कारण खिन्नता बनी रहेगी।

### मिथुन

आज प्रियजनों से अंर्तविरोध की स्थिति उत्पन्न करेगा। आपके समय के अनुसार काम होने में बाधा रहेगी। मौसम भी आज अनुकूल नहीं रहेगा। किन्तु वृष राशि का बृहस्पति सायंकाल में कुछ मन संतोष देगा। बड़ी मात्रा में धन हाथ मिलेगा।

### कर्क

आज आपकी राज्य मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा। शत्रुओं का मनोबल गिरेगा। घरेलू एवं अच्छे गुण वाले लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा। व्यवसाय में भी नौकरों व भागीदारों से अच्छा वातावरण मिलेगा।

### धनु

आज आपको शारीरिक एवं आर्थिक बल प्रदान करेगा। अच्छे गुणवाले लोगों से मेल-मिलाप बढ़ने से अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में रहेंगे। श्रेष्ठ मार्गो से पर्याप्त आमदनी होगी परन्तु व्यय आय के अनुपात में अधिक होगा। रात्रि में किसी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा बनेंगे, खर्च बढ़ेगा।

### मकर

आज व्यापार के सहयोगियों से मनमुटाव की स्थिति होने के कारण पूरा दिन असहज रहेगा। अकारण शत्रु उत्पत्ति, निर्मूल विवाद से आप परेशान रहेंगे। सायंकाल के समय सम्पत्ति से लाभ और पत्नी से उत्तम सहयोग मिलने के कारण संतुष्टि रहेगी। आप अगर सम्पत्ति से जुड़े मामले को लेकर चिंतित हैं।

### सिंह

आज शुभ व्यय और कीर्ति में वृद्धि करेगा। भाग्य का उदय धन-धर्म की वृद्धि होने से खुश रहेंगे। शत्रु चिन्ताओं का दमन, प्रबल से प्रबल विरोधियों के होने पर भी सायंकाल तक हार होगी। आपके धन और कारोबार से जुड़े हुए कार्य पूरे होंगे और आपको धन लाभ होगा।

### कन्या

आज आपको संतान की तरफ से चिन्ता रह सकती है। आज अगर आप कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत इसे टाल दें। आज आपको नौकरी में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कारोबार से जुड़े हुए लोगों को याद रखना होगा।

### कुंभ

आज व्यवसाय में निरन्तर लाभ होने की संभावना बनी रहेगी और व्यवसाय के भागीदारों से परेशानी होने की संभावना भी बनी रहेगी। सायंकाल से लेकर रात्रि तक समीप की यात्रा का योग बना हुआ है। बिजनेस में किसी नए पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको आगे चलकर लाभ होगा।

### मीन

आज आर्थिक लाभ होने की संभावना रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य एवं नम्रता से काम करें। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आज आपके कार्य और अधिकारों में वृद्धि होगी जिससे आस-पास के अन्य सहयोगियों में कड़वाहट बढ़ने से परेशानी हो सकती है।

## संक्षिप्त समाचार

### छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपस में ही भिड़े भाजपा के दो नेता, किस मुद्दे पर हंगामा?

**रायपुर, एजेंसी।** छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब कुरूद से भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अपनी ही पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा से भिड़ गए। बता दें कि बिरकोना में किसान की मौत के मामले में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ध्यानाकर्षण लेकर आए। नारेबाजी के बीच प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विजय शर्मा और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस देखी गई। विपक्ष की नारेबाजी और विजय शर्मा और अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस के बीच सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिरकोना में किसान की मौत के मामले में अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण लाते हुए सवाल किया कि किसान कोमल साहू ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है? यह साफ होना चाहिए क्योंकि शरीर में चोट के निशान थे, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। विजय शर्मा से तीखी बहस के बीच अजय चंद्राकर पिपरिया थाना के पूरे स्टाफ को हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने अजय चंद्राकर की मांग को अस्वीकार कर दिया। हंगामा एवं शोरशराबे को देखते हुए सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि कोमल साहू की मृत्यु को उसके परिजन हत्या बता रहे हैं। इसकी दृष्टि से पूरी मामले की जांच कराई जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया था। साथ ही सात दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, लेकिन जांच में देरी से परिवार असहज है। इसलिए मामले की जल्द से जल्द हत्या के एंगल से जांच कराई जानी चाहिए। पुलिस जांच में हादसे को आत्महत्या बताया जा रहा है। यदि यह आत्महत्या है तो इसमें उकसाए जाने की भी जांच होनी चाहिए।

### यूपी में खोजे जा रहे पासी चेहरे, सपा के बाद अब कांग्रेस एक्टिव

**लखनऊ , एजेंसी।** उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पासी समुदाय को लुभाने में अभी से जुट गए हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा के नेता अपने-अपने तरीकों से पासियों को साध रहे हैं, वहीं अब इस लिस्ट में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पासी नेता मसूरिया दीन की आज पुण्य तिथि मनाई। कांग्रेस की ओर से राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाके मल्लीहाबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह पासी बहुल क्षेत्र है। इस दौरान पार्टी विचारक के रूप में पासियों के सशक्तिकरण के लिए उनके योगदान पर चर्चा की गई। साथ ही, पासी नेताओं की उपस्थिति में सेमिनार भी आयोजित किया गया। मसूरिया दीन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ 1952 और 1957 में 2 बार फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सह-निर्वाचित हुए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम को हटाने को लेकर आंदोलन शुरू करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा, उन्होंने अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए भी काफी काम किया। मालूम हो कि वह संविधान सभा के सदस्य थे और आजादी के बाद विधायक व सांसद चुने गए। पासी समुदाय के लिए आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां जाटवों के बाद पासी दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है। ये लोग राज्य की कुल अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 16 प्रतिशत हैं। खासतौर से अवध इलाके में इस समुदाय की बड़ी उपस्थिति है। ध्यान रहे कि फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा को हराने वाले सपा नेता अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं। हाल ही में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सपा सांसद ने 2 पासी चेहरों (उदा देवी और महाराजा बिजली पासी) का जिक्र किया था। पिछले कुछ चुनावों में ऐसे देखा गया है कि पासी समुदाय ने बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में वोट दिया है।

### अशोक गहलोत फ्री स्मार्टफोन योजना स्थगित, नहीं मिलेगी फ्री में बिजली

**जयपुर, एजेंसी।** राजस्थान में गहलोत राज में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना फिलहाल स्थगित है। जबकि 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों योजनाओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विधानसभा में यह जानकारी दी गई। राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाती रही है। लेकिन अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। फ्री बिजली योजना को पूर्व की गहलोत सरकार ने शुरू किया था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। नए लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। राजस्थान विधानसभा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को अब आगे इस योजना में जोड़ने का कोई स्कीम नहीं है। इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक करीब 98.23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया उन सबको योजना का लाभ दिया गया। बाकी बचे उपभोक्ताओं के लिए कहा कि इस योजना के तहत एख जनाधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन पर ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है।

# यूपी की राजधानी में बिजली संकट, उपकेंद्रों पर हंगामा

**लखनऊ , एजेंसी।** यूपी की राजधानी लखनऊ में बिजली संकट से त्रस्त लोगों ने सोमवार रात को बालाघाट उपकेंद्र पर धावा बोल दिया। गुस्साई भीड़ कंट्रोल रूम के भीतर घुस गई और सभी फीडरों की बिजली सप्लाई बंद करने लगी। इस पर उपकेंद्र पर मौजूद बिजलीकर्मियों ने आक्रोशित लोगों को रोकना चाहा, पर नाराज लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। बवाल बढ़ने पर कई कर्मचारी उपकेंद्र छोड़कर भाग गये। जिसके बाद लोग बालागंज चौराहा जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उग्र भीड़ की पुलिसकर्मियों से भी तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि देर रात तक बिजली सप्लाई चालू नहीं हुई। बिजली संकट को लेकर नाराज लोगों ने रात 1.30 बजे बीकेटी के न्यू कैंपस उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर बाल कृष्ण और दो कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की।

इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बालाघाट उपकेंद्र सोमवार रात 12.30 बजे बालागंज चौराहे पर अंडरग्राउंड केबल फाल्ट हो गया। इससे सरफराजगंज, रस्तोगी नगर, हरदोई रोड सहित आसपास के बड़े इलाके में अंधेरा छा गया। बिजली कर्मचारियों ने राधाग्राम उपकेंद्र से वैकल्पिक बिजली सप्लाई चालू की लेकिन बिजली की मांग बढ़ने पर सभी इलाकों में रोस्टिंग शुरू हो गई। इसके बाद सोमवार दोपहर में बालागंज चौराहे पर सड़क खोदकर केबल फाल्ट दुरुस्त किया गया, लेकिन शाम को फिर बिजली सप्लाई ठप हो गई। इससे घरों में पानी नहीं आया।

परेशान लोगों ने जूनियर इंजीनियर, एसडीओ को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और रात 10 बजे बालाघाट उपकेंद्र पर धावा बोल दिया। भीड़ ने बिजलीकर्मियों के साथ मारपीट की। उग्र भीड़ कंट्रोल रूम के भीतर पहुंचकर सभी फीडरों की बिजली सप्लाई ठप करवा दी। इस दौरान कई कर्मचारी उपकेंद्र छोड़कर भाग गये। इसके बाद गुस्साएं लोग बालागंज चौराहे पर सड़क जाम करने लगे।

इससे लखनऊ हरदोई रोड ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने लाठिया फटकार कर भीड़ को खदेड़ा। हालांकि देर रात तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। आलमबाग के आजाद नगर में सोमवार को रातभर बिजली ठप रही। उमस भरी गर्मी में लोगों ने छत और सड़क पर टहलकर रात गुजारी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली गुल होते ही उपकेंद्र से लेकर इंजीनियरों तक फोन नहीं उठता है।

**तीन दिन से गुल थी बिजली, हत्या के बाद ठीक हो गई लाइन :** बंथरा गांव में तीन दिन से बिजली संकट था। ट्रांसफार्मर एरियर बंच कंडक्टर के तीन सर्किट जल गए थे। कर्मचारियों ने दो सर्किट के तार बदल दिये थे पर तीसरे को बदला तो वह जल गया। इससे तीन दिन से बिजली बाधित थी। अधिशासी अभियंता अवनीश के मुताबिक एरियर बंच कंडक्टर सही न होने से सप्लाई में दिक्कत थी। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली संकट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक की जान चली गई। ग्रामीणों के मुताबिक घटना के बाद बिजली संकट भी दूर हो गया। बिजली विभाग पहले ही चेत जाता तो इस वारदात की नौबत ही न आती।

## सरकार के क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं 100 से ज्यादा कफ सिरप

**नईदिल्ली, एजेंसी।** कफ सिरप को लेकर भारत की फार्मा कंपनियों पर दुनिया के कई देशों में सवाल उठने के बाद अब सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 100 कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गाबिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदारी बताई गई खांसी की सिरप में जो टॉक्सिन मौजूद थी वही टॉक्सिन इन सिरप में भी पाया गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्राइकोल पाए जाने की वजह से 100 कंपनियों के कफ सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की श्रेणी में रखा गया है। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोट में कहा गया है कि डीईजी/ईजी, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, पीएच वॉल्यूम के आधार पर कफ सिरप को एनएसक्यू की श्रेणी में रखा गया है।

**7,087 में से 353 की गुणवत्ता ठीक नहीं :** 7087 बैच दवाओं की जांच की गई जिनमें से 353 को एनएसक्यू की श्रेणी में रखा गया। वहीं 9 सैंपल में डीईजी और ईजी की मात्रा थी। गुणवत्ता ठीक ना होने की वजह में डीईजी और ईजी की उपस्थिति के अलावा असुरक्षित सप्लाई चेन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल बल्क टेस्टिंग में फेल होने को बताया गाय है। कई देशों में बच्चों की मौत के बाद भारत में बनने वाली कफ सिरप पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट लैब्स में इनकी जांच की जा रही है।

**डब्ल्यूएचओ ने उठाए थे सवाल :** विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अक्टूबर 2022 में भारत की कफ सिरप पर सवाल उठाए थे। दरअसल बताया गया था कि गाबिया में कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनी फेल हुईं और 70 बच्चों की मौत हो गई।

## टीएमसी विधायकों को राज्यपाल ने दी वॉर्निंग- तुम्हारी शपथ ठीक नहीं, भरना पड़ेगा जुर्माना

**कोलकाता, एजेंसी।** पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में जीते दो विधायकों की शपथ को राज्यपाल सीवी आनंदबोस ने गलत बताते हुए जुर्माने की चेतावनी दी है। दरअसल दो सप्ताह पहले सायंतिका बनर्जी और रेयाक हुसैन को स्पीकर बिमान बनर्जी ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई थी। अब राज्यपाल ने दोनों विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी शपथ संवैधानिक रूप से अनुचित थी और अगर वे सदन की वोटिंग या फिर कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें एक दिन का 500 रुपया जुर्माना देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक राजभवन द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि नियम पुस्तिका के अध्याय दो की धारा 5 राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकती। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने शपथ दिलाने के लिए डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी को आदेशित किया था हालांकि शपथ स्पीकर बिमान बनर्जी ने दिलवाी है। जब राज्य का संवैधानिक मुखिया किसी को शपथ दिलाने के लिए आदेशित कर रहा है तो स्पीकर कैसे आदेश की अवहेलना कर सकते हैं। दोनों विधायकों ने 5 जुलाई को शपथ ली थी। इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह में संविधान की अवहेलना की गई है।

## हत्या की कोशिश के लिए नहीं हो सकती 10 साल से ज्यादा की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ

**नईदिल्ली, एजेंसी।** सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह साफ कर दिया है कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दस साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आजीवन कारावास की सजा ना मिली हो तो अपराधी को इससे ज्यादा अवधि तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत सज़ा को स्पष्ट करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने हत्या के प्रयास के मामलों के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा का पालन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हत्या के प्रयास के लिए सज़ा के मामले में कानून स्पष्ट है। आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग में अधिकतम दस साल कारावास की सजा निर्धारित की गई है जबकि दूसरे भाग में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, जब कानून ने स्पष्ट शब्दों में धारा 307 आईपीसी के पहले भाग के तहत आरोप साबित होने पर अधिकतम सजा निर्धारित की है और जब संबंधित कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते समय आजीवन कारावास की सजा नहीं दी, तो किसी भी परिस्थिति में दोषी को दी जाने वाली सजा आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग के तहत निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो सकती। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), जो 1 जुलाई से लागू हुई है, की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास को इन्हीं प्रावधानों के साथ बरकरार रखा गया है। अपने फैसले में कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धारा 307 के दूसरे भाग के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाती है, तो एकमात्र दूसरा विकल्प पहले भाग के तहत निर्धारित सजा है। इसमें साफ उल्लेख है कि सजा की अवधि

अधिकतम दस साल तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास की सजा से संबंधित है और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हत्या के प्रयास से संबंधित है, जिसके लिए दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरे भाग में उन स्थितियों का जिक्र है जहां पीड़ित को नुकसान पहुंचा हो, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है।

**सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट :** सुप्रीम कोर्ट में हत्या के प्रयास के एक मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाए गए दो दोषियों की अपील पर सुनवाई चल रही थी। हरियाणा के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल नीरज और एडवोकेट पीयूष बेरीवाल ने तर्क दिया कि शारीरिक चोट की प्रकृति और उसके बाद की स्थिति के हिसाब से दोषियों को 14 साल की जेल की सजा मिलनी चाहिए।

हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने में आनुपातिकता के सिद्धांत को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, धारा 307 का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कानून वास्तव में कुलपे पोएना पर एस्टो के तर्ज पर बना है, जिसका मतलब है दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए या सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए।

## अजित पवार की एनसीपी के पोस्टरों से मुख्यमंत्री ही गायब, क्या बढ़ गई गठबंधन में दरार?

**मुंबई, एजेंसी।** महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सब सही चल रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने तनाव के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहले हार का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा गया। इसके बाद अब विधानसभा सीटों के लिए रस्साकशी तेज है। वहीं अब अजित पवार की एनसीपी की ओर से लड़की-बहिन योजना के पोस्टर लगाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पिछले महीने विधानसभा में अपने बजट भाषण में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना की घोषणा की थी। पवार एकनाथ शिंदे सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। ये पोस्टर सोमवार को पवार के जन्मदिन के अवसर पर अहमदनगर जिले के पारनेर, अहमदनगर, श्रीगोंडा और कर्जत-जामखेड विधानसभा क्षेत्रों के उनके दौरे के दौरान लगाए गए थे।

चारों स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में पवार ने महिलाओं को संबोधित किया और योजना का उल्लेख 'माझी लाडकी बहिन' के रूप में किया गया, जबकि 'मुख्यमंत्री' शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस स्कीम के तहत उन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की रकम दी जाएगी, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होगी। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीते महीने बजट के दौरान स्कीम का ऐलान किया था। वह राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। अजित पवार इस बीच अहमदनगर, श्रीगोंजा, करजात-जमखेद के इलाकों में गए ताकि असेंबली चुनाव से पहले कुछ बढ़त बनाई जा सके। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और इसी दौरान ये पोस्टर सामने आए।

उनके इन दौरों के वक्त ही पिंक कलर में पोस्टर लगाए गए थे। इनमें अजित पवार की तस्वीरें तो थीं, लेकिन सीएम का जिक्र तक नहीं था। इसे लेकर कयास तेज हो गए हैं, लेकिन अजित पवार की एनसीपी की ओर से अब सफाई दी जा रही है। एनसीपी का कहना है कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर विवाद की जरूरत नहीं है। स्कीम का नाम माझी लड़की बहिन है। इसलिए इसका जिक्र बैनरों पर किया गया है। इसमें न तो कोई राजनीति है और न ही किसी का अपमान किया गया है।

## बंगाल भूमि घोटाले में तीसरा टीएमसी नेता गिरफ्तार, सीएम ममता बनर्जी के आदेश पर ऐक्शन

**कोलकाता, एजेंसी।** पश्चिम बंगाल में कथित भूमि घोटाला मामले में तीसरे टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। सोमवार को दार्जिलिंग जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता और नक्सलबाड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। राज्य भूमि और भूमि राजस्व विभाग ने मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद महीनेभर पहले सीएम ममता बनर्जी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने के आदेश दिए थे। गिरफ्तार आरोपी टीएमसी नेता की पहचान असरफ अंसारी के रूप में की गई। अंसारी दार्जिलिंग जिले से गिरफ्तार होने वाले तीसरे सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के नेता हैं। इससे पहले सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के बोर्ड सदस्य और डाबग्राम-फुलबारी सामुदायिक ब्लॉक में टीएमसी उपाध्यक्ष गौतम गोस्वामी को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गोस्वामी पर अध्यक्ष देबाशीष प्रमाणिक का करीबी सहयोगी होने का आरोप लगा था। देबाशीष को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को दार्जिलिंग जिला पुलिस ने सिलीगुड़ी क्षेत्र में सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गोस्वामी और प्रमाणिक से पूछताछ के बाद असरफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अंसारी ने मीडिया से कहा, मैं एक साजिश का शिकार हूं। मैं स्थानीय आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। महीनेभर पहले सीएम ममता ने दिए थे आदेश सिर्फ यही नहीं भाजपा नेता और पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व जिला सचिव उत्तम रॉय को सरकार द्वारा निहित भूमि पर अवैध रूप से एक रिसॉर्ट स्थापित करने के आरोप में 6 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारियां मुख्यमंत्री ममता द्वारा 6 जून की प्रशासनिक बैठक में कड़ी चेतावनी देने के लगभग एक महीने बाद की गई है। ममता ने तब बैठक में कहा था, डाबग्राम-फुलबारी क्षेत्र में एक भू-माफिया ऐक्टिव है। मुझे कई शिकायतें मिली हैं। इसमें भू-राजस्व अधिकारी भी शामिल हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि भू-माफियाओं ने कई भूखंडों को कई-कई बार बेचा है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आदिवासी समुदायों के स्वामित्व वाली भूमि के पात्रों को भी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। इस मामले में जांच जारी है।

## चुनावी मोड में भाजपा, संगठनात्मक बैठक बुलाई, तीन राज्यों पर होगा फोकस

**नईदिल्ली, एजेंसी।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दो दिवसीय संगठनात्मक बैठक बुलाई है। यह बैठक गुरुवार से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विभिन्न राज्यों के चुनावी मुद्दों, संगठनात्मक ढांचे की मजबूती, और मतदाताओं तक पहुंच बनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा होगी। भाजपा की संगठनात्मक बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे तीन राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीन राज्यों में से दो पर वर्तमान में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का शासन है। इस बैठक में इन तीनों राज्यों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि इन चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से काफी नीचे रहा है। हालांकि पार्टी पहले ही चिंतन शिविर आयोजित कर चुकी है, लेकिन इस बात की चिंता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इस तरह की गलतियों से कैसे बचा जा सके।

बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के कारण पहले से ही मंथन एवं समीक्षाओं का दौर चल रहा है। इसके अलावा, 'संगठन एवं सरकार में बड़ा कौन'' मुद्दा भी गर्माया हुआ है। इन सबके बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस दौरान

चौधरी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य में पार्टी के संगठनात्मक मामलों से संबंधित कई मुद्दों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले कम सीटें पाने के बाद भाजपा के भीतर अलग-अलग आवाजें उठ रही हैं। इन सबके बीच चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से अलग-अलग मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मौर्य के बीच मतभेदों की खबरों को तब हवा लगी जब मौर्य ने 14 जुलाई को लखनऊ में हुई पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कहा कि 'संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है'। उनके बयान को आदित्यनाथ पर हमले के रूप में देखा गया। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चुनावी हार के लिए ''अति आत्मविश्वास'' को भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रचार अभियान का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। बहरहाल, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मौर्य और चौधरी से बात करने की पहल को आगामी चुनावों से पहले संगठन में खामियों को दुरुस्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रदर्शन और भाजपा को लगे झटके के बाद संगठन में चल रही खींचतान भाजपा के लिए चिंता का सबब बनी हुई है।

# ओलंपिक में मेडल को दांतों से क्यों काटते हैं खिलाड़ी... क्या यह कोई नियम है?

**नईदिल्ली, एजेंसी।** पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज इसी हफ्ते 26 जुलाई को होगा. यह गेम्स 11 अगस्त तक चलेंगे. इस बार ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे. इनसे रिकॉर्ड मेडल जीतने की उम्मीद है. मगर यहां हम कुछ जरा हटकर बात करने वाले हैं. यह किसी एथलीट के मेडल जीतने के बाद उसे दांतों से काटने के बारे में है. ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ या फिर एशियन गेम्स... फैन्स ने अक्सर पोडियम पर खड़े होकर अपने मेडल को काटते हुए एथलीट्स की तस्वीरें देखी हैं. अब सवाल यह भी है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जब कोई एथलीट मेडल जीतता है, तो वो पोडियम पर खड़े होकर उसे दांतों से क्यों काटता है?

### जब मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के चलते थे

क्या यह कोई नियम है या कोई परंपरा है? फैन्स हमेशा ही इस सवाल को लेकर कन्फ्यूज और जवाब जानने को उत्सुक होते हैं. मगर जब इसी सवाल को मन में लेकर जब इतिहासकारों की बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो माजरा कुछ अलग ही दिखता है.

इतिहास के मुताबिक, पुराने समय में जब मुद्रा के रूप में कीमती धातु का इस्तेमाल होता था. तब सोने के सिक्कों की प्रामाणिकता की जांच के लिए व्यापारी उनको काटते थे. क्योंकि सोना नरम धातु है और थोड़े ही दबाव में फट सा जाता है. यदि उसे कुतरा जाए तो वो अपनी छाप छोड़ देता है. 1912 के बाद सोने के शुद्ध मेडल देना बंद हुआ मगर मेडल को दांतों से काटने का मतलब उसकी शुद्धता की परख करना नहीं होता है. खिलाड़ियों के बारे में ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा. बता दें कि 1912 से पहले शुद्ध सोने के मेडल दिए जाते थे. मगर इसके बाद से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने शुद्ध स्वर्ण पदक देना बंद कर दिया था.

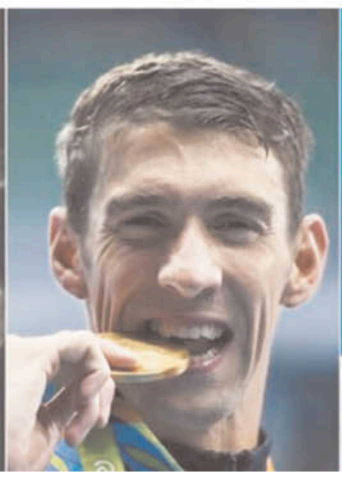

मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेडल को दांतों से काटने के कारण ऐसा किया है. ऐसा भी कहा जाता है कि 1912 से पहले भी एथलीट मेडल को अपने दांतों से काटते थे. तब वे सोने की शुद्धता के लिए करते थे. मगर यह परंपरा 1912 के बाद अब भी कायम है. हालांकि अब मेडल को दांतों के काटने के पीछे दूसरी धारणा मानी जाती है. कहा जाता है कि एथलीट ऐसा करके अपनी प्रतियोगिता में उनकी कड़ी मेहनत, टक्कर और जोश को दर्शाता है.

इसके अलावा एथलीट अपने मेडल को दांतों से क्यों काटते हैं इसको लेकर ओलंपिक की वेबसाइट पर भी एक जानकारी दी गई है. ओलंपिक के मुताबिक एथलीट सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए मेडल को दांतों से काटते हैं. जब एथलीट अपना मेडल लिए पोडियम पर खड़े होते हैं, तब फोटोग्राफर उनसे मेडल दांतों से काटने जैसा पोज बनाने को कहते हैं.

### ● फोटोग्राफर के लिए एथलीट ऐसा पोज देत हैं

इसको लेकर फोटोग्राफर का मानना कुछ अलग ही होता है. वो हमेशा ही एथलीट से इस पोज की मांग करते हैं. फोटोग्राफर के लिए यह पोज एक शान होती है और उनका मानना है कि यह शानदार पोज अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर छपेगा. यही कारण है कि फोटोग्राफर खुद ही एथलीट्स से इस पोज की अपील करते हैं. इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक हिस्टोरियंस के पूर्व अध्यक्ष डेविड वालेचिन्स्की ने सीएनएन को बताया था, यह फोटोग्राफरों के लिए एक जरूरी पोज बन गया है. मुझे लगता है कि वे इसे एक प्रतिष्ठित शॉट के रूप में देखते हैं, जिसे शायद वे आसानी से बेच सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा कुछ है जो एथलीट खुद से करें.

## संक्षिप्त समाचार

### भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा।

**आईओसी अध्यक्ष ने दी बधाई**

आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाच ने बिंद्रा को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने ओलंपिक आंदोलन में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है।

**खेल मंत्री ने दी बधाई**

वहीं, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई! उनकी उपलब्धि हमें गर्व से भर देती है और वे वास्तव में इसके हकदार हैं। उनके नाम ने ही निशानेबाजों और ओलंपियनों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है।

### चामरी अटापट्टू ने महिला एशिया कप में जड़ा ऐतिहासिक शतक

**नई दिल्ली, एजेंसी।** कप्तान चामरी अटापट्टू के नाबाद शतक के बाद शशिनी गिमहानी के फिरकी के जादू से श्रीलंका ने महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के में मलेशिया को 144 रन से रौंदकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। श्रीलंका ने कप्तान चामरी की 69 गेंद में 14 चौकों और सात छक्कों से करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 119 रन की पारी की मदद से चार विकेट पर 184 रन बनाए। चामरी ने हर्षिता समरविक्रम (26) के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 और अनुष्का संजीवनी (31) के साथ तीसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की। बता दें कि चामरी अटापट्टू महिला एशिया कप में शतक जड़ने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं।

मलेशिया की ओर से विनिफ्रेड दुरईसिंगम सबसे सफल गेंदबाज रही जिन्होंने 34 रन देकर दो विकेट चटकाए। इसके जवाब में मलेशिया की टीम 15 साल की बाएं हाथ की स्पिनर गिमहानी (नौ रन पर तीन विकेट), कविषा दिलहारी (चार रन पर दो विकेट) और काव्या काविन्दी (सात रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 19.5 ओवर में सिर्फ 40 रन पर ढेर हो गई। मलेशिया की ओर से एल्सा हंटर (10) ही दोहरे अंक में पहुंच पाई। ग्रुप के एक अन्य मैच में बांग्लादेश ने थाईलैंड को सात विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की।

# स्कॉटलैंड के चार्ली कैसल ने तोड़ा कगिसो रबाडा का रिकॉर्ड

## एकदिवसीय डेब्यू पर 7 विकेट लेकर रचा इतिहास

**नई दिल्ली, एजेंसी।** स्कॉटलैंड के तेज गेंदबाज चार्ली कैसल ने सोमवार को अपने डेब्यू मैच में ही एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया। चार्ली कैसल ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के एक मैच में ओमान के खिलाफ 5.4 ओवर में 21 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

कैसल को टीम में एक अन्य तेज गेंदबाज क्रिस सोल की जगह पर लिया गया था। क्रिस सोल व्यक्तिगत कारणों से उपलब्ध नहीं थे। कैसल ने अपनी पहली ही गेंद पर पूर्व ओमान कप्तान जीशान मसूद को एलबीडब्ल्यू आउट कर धमाकेदार शुरुआत की। अपनी दूसरी गेंद पर उन्होंने अयान खान को बोल्ड कर दिया। यह पहला मौका था, जब किसी गेंदबाज ने एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली दो गेंदों पर दो विकेट लिए हो। कैसल का शानदार डेब्यू जारी रहा और उन्होंने 18वें ओवर में महरान खान को आउट कर पांच विकेट पूरे किए।

इसी के साथ वह उन चुनिंदा 15 गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिन्होंने एकदिवसीय डेब्यू पर पांच विकेट लिए हैं। लेकिन कैसल की गेंदबाजी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ओमान के निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी जल्द आउट कर दिया, और अपने पहले वनडे मैच में 21 रन देकर 7 विकेट चटकाए। यह एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। इससे पहले यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा के नाम था, जिन्होंने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच पर 6 विकेट लिए थे।

रबाडा ने तब 16 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

कैसल अब एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन की सूची में सातवें स्थान पर हैं। ओमान की पूरी टीम 21.4 ओवर में 91 रन पर सिमट गई। ओमान की ओर से प्रतीक अठावले ने सर्वाधिक 34 रन बनाए, और उनके अलावा केवल दो ही बल्लेबाज ऐसे रहे, जिन्होंने दहाई का आंकड़ा छुआ। स्कॉटलैंड की टीम ने यह लक्ष्य 8 विकेट और 196 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया।

**पेरिस ओलंपिक**

## पेरिस ओलंपिक से पहले सुमित नागल की शानदार जीत

### ● क्लेन को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

**नई दिल्ली, एजेंसी।** नागल ने पहला सेट जीता लेकिन क्लेन ने दबदबा बनाकर दूसरे सेट को आसानी से अपने नाम कर लिया। विश्व रैंकिंग में 80वें स्थान पर काबिज नागल निर्णायक तीसरे सेट में 3-5 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए मैच को टाई-ब्रेक तक खींचा।

पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से होगी।

इससे पहले भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने सोमवार को ऑस्ट्रिया में एटीपी 250 कित्जबुहेल ओपन के शुरुआती दौर में स्लोवाकिया के लुकास क्लेन को संघर्षपूर्ण मुकाबले में हरा दिया। ओलंपिक की तैयारियों में जुटे नागल ने 6-4, 1-6, 7-6 (3) से जीत दर्ज की। आगामी टूर्नामेंट से पहले यह उनकी शानदार जीत है। नागल ने पहला सेट जीता लेकिन क्लेन ने दबदबा बनाकर दूसरे सेट को आसानी से अपने नाम कर लिया।

विश्व रैंकिंग में 80वें स्थान पर काबिज नागल निर्णायक तीसरे सेट में 3-5 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए मैच को टाई-ब्रेक तक खींचा। टाई-ब्रेक में नागल एक बारे फिर लय हासिल करने में सफल रहे और 7-3 की जीत के साथ प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। अंतिम 16 में उनके सामने स्पेन के चौथी वरीयता प्राप्त पेड्रो मार्टिनेज की चुनौती होगी। मार्टिनेज विश्व रैंकिंग में 45वें स्थान पर है।

**एमएलसी: 2024**

## महिला प्रशंसक के कंधे पर लगा कीरोन पोलार्ड का सिक्स, मिलकर मांगी माफी

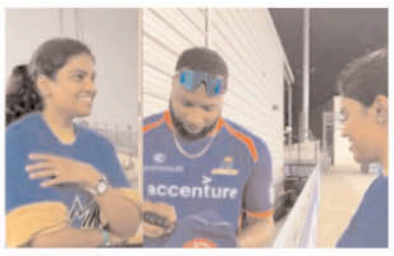

**नईदिल्ली, एजेंसी।** एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने अपने व्यवहार से दर्शकों का दिल जीत लिया। दरअसल, इस समय अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट 2024 चल रही है।

टूर्नामेंट का 19वां मैच एलए नाइट राइडर्स और एमआई न्यूयॉर्क के बीच हुआ। मैच के दौरान पोलार्ड द्वारा स्टैंड में लगाया गया छक्का एक महिला प्रशंसक को लगा। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने न सिर्फ फैन के बारे में पूछताछ की, बल्कि उससे मिलने भी गए।

टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम में आई एमआई न्यूयॉर्क की फैन के हाथ में झंडा भी था। महिला फैन जब चोटिल हो गई तो मैच के बाद पोलार्ड उससे मिलने पहुंचे। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और महिला और उसके पति के साथ सेल्फी ली। इस दिल छू लेने वाली बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पोलार्ड ने प्रशंसक से मुलाकात करते हुए कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक माफी मांगता हूं। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं।

## हैलो इंडिया, आइए एक साथ आएं- पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय एथलीट्स के लिए बोले ऋषभ पंत

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं। भारतीय दल, जिसमें 117 एथलीट शामिल हैं, पेरिस में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ पदक जीतने पर नजर लगाए होंगे, जो 26 जुलाई से शुरू होगा।

ग्रीष्मकालीन खेलों से पहले, टी20 विश्व कप चैंपियन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एथलीटों के लिए एक वीडियो संदेश साझा किया और इसे कैप्शन दिया- पेरिस में तिरंगा ऊंचा लहराए। हमारे भारतीय ओलंपिक एथलीटों को पेरिस 2024 के लिए शुभकामनाएं।

पंत ने वीडियो संदेश में कहा कि हैलो इंडिया, आइए एक साथ आएं और हमारे

भारतीय ओलंपिक एथलीटों का समर्थन करें जो हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए वर्षों से अथक प्रयास कर रहे हैं। आइए उनकी कड़ी मेहनत के लिए अपनी सराहना दिखाएं वे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चमकते हैं। भारत ने टोक्यो संस्करण में एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य सहित सात पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ पदक हासिल किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी भारतीय ओलंपिक संघ को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारतीय एथलीटों के समर्थन में सामने आया है।

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पिछले रविवार को घोषणा की कि बोर्ड अभियान के लिए आईओए को 8.5 करोड़ रुपये प्रदान करके भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 दल का समर्थन करेगा। शाह ने एक्स के पास जाकर निर्णय की घोषणा की और भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दीं।

# टी-20 विश्व कप 2024 से आईसीसी को 167 करोड़ का नुकसान

**नईदिल्ली, एजेंसी।** टी20 विश्व कप आयोजन ने आईसीसी के कुछ पदाधिकारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। समझा जाता है कि आईसीसी को न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डलास में मैचों के आयोजन पर दो करोड़ डॉलर (करीब 167 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ है। पता चला है कि टूर्नामेंट के अमेरिकी चरण के लिए आवंटित बजट लगभग 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर था।

यह पाया गया कि बजट में काफी इजाफा हुआ। इस पर आईसीसी के कुछ प्रभावशाली बोर्ड सदस्यों ने आपत्ति जताई। खराब स्तर की 'ड्रॉप इन' पिचों, टिकट प्रणाली और साजो-समान से जुड़े मुद्दों ने आईसीसी की परेशानी और बढ़ा दी है। विभिन्न निविदाएं सौंपे जाने को लेकर भी चिंता जताई गई है। समझा जाता है कि समिति आईसीसी के कुछ शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका की भी गहन जांच करेगी।

### अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड पर लटकी निष्कासन की तलवार

आईसीसी के प्रतियोगिता प्रमुख क्रिस टेटली ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, आधिकारिक कारण यह बताया गया था कि हर साल होने वाले आईसीसी के प्रमुख टूर्नामेंटों (पुरुष और महिला) का असर पड़ रहा है। आईसीसी ने टी20 विश्व कप के आयोजन की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।

समिति में न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर ट्वोस और आईसीसी के अन्य दो निदेशक लॉसन नायडू तथा इमरान ख्वाजा को जगह मिली है। 'आईसीसी के अनुसार, 'आईसीसी बोर्ड पुष्टि करता है कि टी-20 विश्व कप के आयोजन की समीक्षा होगी।

आईसीसी के एसोसिएट सदस्यता मानदंडों के अनुसार, यूएसएसी दो नियमों संचालन (2.2 बी (द्व)) और प्रशासन तथा कार्यकारी ढांचे (2.2 बी पर खरा नहीं उतरता। पता चला है कि यूएसएसी ने यूएसए ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (यूएसओपीसी) के मानदंडों का पालन नहीं किया है, जो 2028 में लॉस एंजिल्स खेलों का हिस्सा बनने के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय (एनजीबी) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, जहां क्रिकेट पदक कार्यक्रमों में से एक है।

### रद्द हो सकती है यूएसएसी की मान्यता

यदि यूएसएसी, अपने वर्तमान स्वरूप में यूएसओपीसी दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स आयोजकों को पूर्व की मान्यता रद्द करने और एक नया एनजीबी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा कारण सीईओ की नियुक्ति न होना माना जाता है, जो किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए जरूरी है। बयान के मुताबिक, 'अमेरिका क्रिकेट और क्रिकेट चिली को औपचारिक रूप से नोटिस दिया गया है और आईसीसी सदस्यता मानदंडों के अपने वर्तमान गैर अनुपालन को सुधारने के लिए उन्हें 12 महीने का समय दिया गया है।'

# जवाबदेही के साथ दायित्वों का निर्वहन करें विभागीय अधिकारी : कलेक्टर

**पन्ना।** कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक में विभागवार विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर समयावधि में निराकरण के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी जवाबदेही के साथ दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने लंबित टीएल, जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों तथा शासन की प्राथमिकता वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं में तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायत का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए। राजस्व विभाग की अधिक संख्या में लंबित शिकायतों के मद्देनजर राजस्व महाअभियान 2.0 के दौरान ही शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करने का प्रयास हो। बैठक में न्यायालय में लंबित अवमानना याचिकाओं के प्रस्तुत जवाब सहित गेहूं व मसूर एवं सरसों उपार्जन, खुले बोरवेल को ढंकने संबंधी कार्यवाही, केन-बेतवा लिंक परियोजना व रेलवे लाइन के मुआवजा वितरण, अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए डाटा अपडेशन कार्य इत्यादि के संबंध में भी जरूरी निर्देश दिए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी को संबंधित विभाग से समन्वय कर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने टीएल बैठक में शासकीय शालाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। इस संबंध में सभी शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा। अपरिहार्य स्थिति में शिक्षकों के अवकाश की स्थिति में अवकाश आवेदन आवक पंजी में दर्ज करने तथा शालाओं के निरीक्षण के लिए जिला अधिकारियों सहित विभागीय मैदानी अधिकारियों की तैनाती के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूल की भूमि सहित अन्य शासकीय विभागों की जमीन पर अतिक्रमण की स्थिति में तत्काल अवगत कराने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षक भू-अभिलेख को समग्र भूमि ई-केवायसी कार्य की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। साथ ही नालों से अतिक्रमण हटाने, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुराने जल स्त्रोतों के मरम्मत की कार्यवाही तथा वर्षा राहत बचाव कार्य, परियोजनाओं के लिए वन भूमि के हस्तांतरण, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध

में विभागवार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी प्रेषित करने तथा कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में नामांकन की स्थिति और पुस्तक वितरण इत्यादि के संबंध में भी जानकारी ली।

कलेक्टर ने कहा कि वर्षा ऋतु में आयोजित किए जा रहे वृहद स्तरीय वृक्षारोपण महाअभियान में सभी के सहयोग से विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है, लेकिन पौधे के साथ एप पर फोटो अपलोड करने की प्रगति कम है। पौधरोपण उपरांत वायुदूत (अंकुर) एप पर फोटो अपलोड करना भी जरूरी है। इसलिए लक्षित वर्गसमूह से इसका पालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि आगामी 31 जुलाई तक एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी निर्धारित लक्ष्य अनुसार पौधे रोपे जाना है। अब तक 16 हजार से अधिक पौधों की फोटो अपलोड की गई है। वन विभाग को भी पौधारोपण के दौरान प्रत्येक पौधे की फोटो अपलोड कराने के निर्देश दिए गए। टीएल बैठक में अब तक कम वर्षा के दृष्टिगत कृषि कार्य की तैयारियों व खाद-बीज उपलब्धता के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले में अब तक 66 प्रतिशत बोवनी का कार्य हो चुका है। जिला कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पदाभिहित अधिकारियों को समय-सीमा में नागरिक सेवाओं के प्रदाय के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर ने बैठक में वर्चुअल शामिल हुए राजस्व अधिकारियों से आगामी 31 अगस्त तक चलाये जा रहे राजस्व महाअभियान 2.0 की प्रगति की जानकारी लेकर निर्देश दिए कि अभियान के दौरान आने वाले आवेदनों के साथ जिले में आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित सभी प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करें। यदि राजस्व संबंधित नामांतरण, सीमांकन, खसरा, बंटवारा बिना किसी वैध कारण के रोका जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह अनरजिस्टर्ड केस, खारिज केस, आदेश, अमल ना होना, नामातंरण, त्रुटि सुधार आदि से संबंधित आवश्यक आवेदनों में कार्यवाही लंबित रखने पर भी कार्यवाही होगी। सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निश्चित समय में अभियान 2.0 के अंतर्गत अधिक से अधिक लंबित प्रकरण एवं आने वाले आवेदनों का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही राजस्व महाअभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है।

कलेक्टर ने कहा कि एक सप्ताह में समग्र आधार ई-केवायसी पूर्ण करने के लिए कार्य में तेजी लाएं। नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर कार्य पूर्ण करें। जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को नगरीय क्षेत्रों में कार्य की मॉनीटरिंग के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों की पेंशन एरियर राशि भुगतान के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा। कलेक्टर ने संबल पंजीयन की समीक्षा कर अनिवार्य रूप में सात दिवस में आवेदन का निराकरण करने और सत्यापन कार्य के बाद प्रत्येक स्तर पर लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए मॉनीटरिंग के लिए निर्देशित किया। परिवार व सदस्य की समग्र आईडी के आधार से लिंक कार्य के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मंगलवार को ग्राम पंचायतों की जनसुनवाई में भी रोजगार सहायक और सचिव द्वारा उक्त कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित अधिकारी कार्य की मॉनीटरिंग कर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के चिन्हित हितग्राहियों को विभिन्न विभागों की आठ योजनाओं का लाभ प्रदान करने, अजयगढ़ में अजयपाल किला पहुंच मार्ग के लिए वाइल्ड लाइफ स्वीकृति की कार्यवाही, औषधि निरीक्षक को जिले के मेडिकल स्टोर के निरीक्षण तथा उप पंजीयक को वेंडर्स के बैठक स्थान के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय, उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व मोहित सूद सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

## अजयगढ़ में जन्म-मृत्यु ऑनलाइन पंजीयन के संबंध में हुआ प्रशिक्षण

**पन्ना।** जन्म-मृत्यु ऑनलाइन पंजीयन की नवीन प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से पन्ना जिले में द्वितीय चरण में विकासखण्डवार प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। आज अजयगढ़ में तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में इसका प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान रीवैम्प्ड सीआरएस पोर्टल पर संबंधित इकाई द्वारा पंजीयन के कार्य को सरलता एवं सुगमतापूर्वक करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पंजीयन कार्य के दौरान तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण के बारे में भी बताया गया। इस दौरान अजयगढ़ विकासखण्ड के समस्त ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक एवं शाखा प्रभारी जन्म-मृत्यु भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षक उमेश कुमार कुशवाहा, विजय कुशवाहा एवं अवधेश मिश्रा ने प्रशिक्षण प्रदान किया। सहायक सांख्यिकी अधिकारी राजीव पटेल ने बताया कि आगामी दिवसों में जिले के शेष चार विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर गत दिवस प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है।

## पीएम केन्द्रीय विद्यालय पन्ना में एक पेड़ मां के नाम वनोत्सव का आयोजन

**पन्ना।** पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय पन्ना में 22 जुलाई को पौधरोपण महाअभियान की गतिविधियों के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर सुरेश कुमार और विद्यालय के प्राचार्य अमित दाहिया सहित शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। एक पेड़ मां के नाम वनोत्सव कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ पौधरोपण किया गया। प्राचार्य एवं शिक्षकों ने भी पौधे लगाकर सुरक्षा का संकल्प लिया। विद्यालय परिसर के बाहर अशोक, कचनार, गुलमोहर,

आंवला आदि के कुल 20 पौधे लगाए गए। सभी पौधों की फोटो को वायुदूत एप पर अपलोड किया गया। विद्यालय परिसर के अंदर एवं बाहर अब तक पौधरोपण अभियान के अंतर्गत 105 पौधे लगाए जा चुके हैं। विद्यालय परिसर के बाहर पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। कलेक्टर ने पौधरोपण महाभियान के तहत 'एक पेड़ मां के नाम' के अंतर्गत विद्यालय में चलाए जा रहे अभियान के लिए प्राचार्य अमित दाहिया के प्रयासों की सराहना की तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रखने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताने के साथ ही सभी विद्यार्थियों को अपने घरों में खाली जमीन पर पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया।

## जिले में 281.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज

**पन्ना।** अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार पन्ना जिले में इस वर्ष 1 जून से 22 जुलाई तक 281.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। गत वर्ष उक्त अवधि में 322.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी। अब तक सर्वाधिक वर्षा पवई में 372 मिमी और सबसे कम देवेन्द्रनगर में 204 मिमी दर्ज की गई है, जबकि वर्षामापी केन्द्र पन्ना में 303 मिमी, गुनौर में 250.1 मिमी, अमानगंज में 298.3 मिमी, सिमरिया में 310.8 मिमी, शाहनगर में 213.6 मिमी, रैपुरा में 360.4 मिमी तथा अजयगढ़ में 224.8 मिमी कुल वर्षा दर्ज की गई है। पन्ना जिले की औसत वर्षा 1176.4 मिमी है।

## बोरी पुल के खस्ता हाल, सैकड़ो साल पुरना पुल पहुंचा छतिग्रस्त की इस्थित में

### बोरी नदी के पुल पर एक बड़े हादसे की संभावना

**सलेहा।** सलेहा से देवेन्द्रनगर सड़क मार्ग में सैकड़ों वर्ष पुराना पुल अब उम्र दराज होने से छति की स्थिति में है सलेहा से देवेन्द्रनगर को जोड़ने वाला यह सीधा सड़क मार्ग है जो सलेहा से तीन किलोमीटर दूरी पर ग्राम बछरवारा के पास बोरी नदी के पुल के नाम से जाना जाता है यह पुल सैकड़ों वर्ष पुराना है एवं पुरानी वस्तु कला के अनुसार बना है अब यह पुल उम्र दराज होंने से क्षति की इस्थित में है विगत वर्ष इस पुल का एक हिस्सा आधा छति हो गया था जिसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे विगत वर्ष सड़क विभाग द्वारा सीमेंट की खाली बोरियों में मिट्टी भर कर छति ग्रस्त हिस्से में लगा दी गई थी जो इस वर्ष की भीषण गर्मी में सीमेंट की बोरी

खराब होकर फट गई है जिनमें भरी मिट्टी खिसकने लगी है पुल की इस्थित विगत वर्ष जैसे फिर से बन गई है अब इस पुल मे पानी के उफान को झेलनी की दागत नहीं है यह पुल कभी भी प्राकृतिक पानी के सैलाब से टूट सकता है इस पुल से सैकड़ों भारी भरकम वाहन दिन रात गुजरते है तथा सैकड़ों गांवों इस्कूली छात्र छात्राओं से लेकर सभी जनमानस एवं पशुओं का सलेहा से संम्पर्क बना रहता है पुल उम्र दराज होने के साथ एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाना कभी भी पुल ढहने के संकेत देता है एवं आवागवन में बड़े हादसे जैसे संदेह को बनाए रखता है इस पुल एवं सड़क मार्ग का भी लेवल समतल है और कोई पुल पर डिवाइडर नहीं बने हैं जो कभी भी किसी को हादसे की अगुवाई वाली दवात देने जैसे है शासन प्रशासन को इस पुल का अवलोकन कर फिल हाल पुख्ता इंतजाम करतें हुए डिवाइडर खड़ा कर आवागवन सुलभ बनाएं रखने के साथ बड़े हादशे जैसी घटनाओं को रूकने का प्रयास करना चाहिए एवं सैकड़ों वर्ष पुराने पुल की जगह नया बेहतर तकनीक से निर्मित पुल बनाना चाहिए।

## स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ

पन्ना

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर नवीन उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। योजना के तहत पात्र आवेदक राज्य शासन की बैंक वित्त पोषित योजनाओं के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा गुणदोष के आधार पर प्रकरण बैंक शाखाओं को अग्रेषित किये जायेंगे। योजना एवं आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र पन्ना से संपर्क कर सकते हैं।

## आहरण संवितण अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 25 एवं 26 जुलाई को

**शहडोल।** कलेक्टर श्री तरूण भटनागर ने समस्त आहरण संवितरण अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि वर्तमान में समस्त आहरण सतिहरण अधिकारियों द्वारा विगल 5 वर्षों से वित्तीय प्रबंधतन/कोषालयीन संव्यवहार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली आईएफएमआईएस के माध्यम से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हाथरारकी के माध्यम से क्रियेटर व्हेरीफायर एवं अप्रूवर बनाया जाकर सुरक्षित कार्य निष्पादन किया जाना है। किन्तु आज भी आहरण संवितरण अधिकारी एवं संबंधित शाखा सहायको, क्रियेटर, व्हेरीफायर अप्रूवर दारा आईएफएमआईएस का विधिवत संचालन दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है जबकि आईएफएमआईएस लागिन में विभिन्न मॉड्यूल के सुचारू संचालन हेतु यूजर मैनुअल दिए गए है। जिसके तहत पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेस द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम मे आईएफएमआईएस का विधिवत संचालन एवं सुरक्षित सव्यवहार के दष्टिगत समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों हेतु 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 एवं 26 जुलाई 2024 को ई-दक्ष केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में 2 चरणों में प्रात: 11: बजे से 1:30 एवं दोपहर 2 बज से 4:30 तक आयोजित किया जाएगा।

## महारानी दुर्गा राजलक्ष्मी विद्यालय में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगित संपन्न

**पन्ना।** शिक्षा विभाग द्वारा शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन जिले भर मे किया गया था। जिसमें ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राओं की जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता महारानी दुर्गा राजलक्ष्मी विद्यालय में आयोजित की गई थी। उक्त प्रतियोगित में जूनियर वर्ग के 14,17,19 वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा भाग लिया गया था तथा खिलाडीयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतियोगित मे नब्बे खिलाड़ियों द्वारा सहभागिता निभाई गई है। महारानी दुर्गा राजलक्ष्मी विद्यालय के प्राचार्य और उनके विद्यालय के पी टी आई पहलवान सिंह द्वारा एक अच्छे खेल माहौल में प्रतियोगिता संपन्न कराने में अहम भूमिका अदा की। उक्त जिला स्तरीय प्रतियोगिता में एन के मिश्रा सेवानिवृत पी टी आई, शिवकुमार मिश्रा, मनोज खरे, टेक बहादुर सिंह, पहलवान सिंह, शमीम सिद्दीकी, निखिल सोनी, रेनबो स्कूल देवेंद्रनगर के खेल शिक्षक देशराज सिंह घोषी और राजेश मिश्रा जिला क्रीड़ा अधिकारी उपस्थित रहे।.

## दिव्यांग को वैशाखी का वितरण

**पन्ना।** सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जरूरतमंद दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं के तहत वैशाखी एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है। समय-समय पर दिव्यांगजनों के लिए शिविर भी लगाए जाते हैं। इस क्रम में आज जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र में ग्राम रहुनिया गुर्जर निवासी जरूरतमंद दिव्यांग पप्पू सिंह को वैशाखी का वितरण किया गया।

## वन स्टॉप सेन्टर द्वारा दी गई बाल विवाह व घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी

**पन्ना।** जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी उदल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में वन स्टॉप सेन्टर सखी पन्ना की प्रशासक मीरा लोधी व परामर्शदाता प्रियंका सिंह, केस वर्कर शिवानी शर्मा, सत्या पाठक व कम्प्यूटर ऑपरेटर साहिद खान, साईबर ऑफिस से आशीष अवस्थी एवं अरविन्द त्रिपाठी द्वारा महारानी दुर्गा राज्य लक्ष्मी स्कूल तथा कस्तूरबा गांधी छात्रावास पन्ना में घरेलू हिंसा, साइबर क्राईम, बाल विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान सखी सेन्टर के संचालन संबंधी जानकारी भी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि सरकारी स्तर पर जो योजनाएं

चल रही हैं, उनमें वन स्टॉप सेंटर सखी योजना बहुत कारगर है। इस योजना का उद्देश्य लिंग के आधार पर हिंसा झेलने वाली महिलाओं को तुरंत और हर तरह की मदद उपलब्ध कराना है। घर से लेकर दफ्तर तक महिलाओं को लिंग के आधार पर कई बार भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसमें ऑनर किलिंग, दहेज प्रताड़ना, एसिड अटैक, लिंग के आधार पर गर्भपात और भेदभाव इत्यादि शामिल है। इस तरह की घटनाओं को रोकने और इसके खिलाफ महिलाओं को मजबूती से खड़ा करने के मकसद से ही वन स्टॉप सेंटर योजनाओं जिसे सखी नाम से भी जाना जाता है, को शुरू किया गया है। वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन शोषण का सामना कर रही हैं।

सेंटर के माध्यम से घर, दफ्तर या किसी भी अन्य जगह लिंग के आधार पर हिंसा झेलने वाली महिलाओं को तुरंत कानूनी और मेडिकल सहायता के साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी प्रदान की जाती है।

## एकीकृत शाला निधि का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देश

### राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी कलेक्टर को जारी किये निर्देश

**पन्ना।** समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एकीकृत शालाओं की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिये एकीकृत शाला निधि का समुचित उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। वार्षिक अनुदान अब शाला में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर जारी होगा। एकीकृत शाला निधि का उपयोग शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है।

एकीकृत शाला निधि का उपयोग शालाओं की स्वच्छता, बस्तामुक्त, बालसभा, यूथ एण्ड ईको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र एवं स्कूल के आसपास की खोज जैसी गतिविधियों पर मुख्य रूप से किया जायेगा। इसके साथ ही शाला निधि का उपयोग खेलकूद और बालिकाओं के आत्म प्रशिक्षण पर भी मुख्य रूप से खर्च किया जायेगा। निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय में ग्रीन बोर्ड छात्राओं के बैठने के लिये समुचित व्यवस्था, शालाओं की बुनियादी सुविधाओं पर आवश्यक खर्च और शालाओं में नियमित सफाई की व्यवस्था पर किया जायेगा। एकीकृत शाला में पढ़ने वाले छात्रों की पाठ्य पुस्तकें और कॉपी वर्ष भर विद्यार्थियों के पास सुरक्षित रहें, इसके लिये शिक्षकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। सामग्री क्रय करते समय स्वसहायता समूह को प्राथमिकता दी जायेगी। एकीकृत शालाएँ अब कक्षा 1 से 8, कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 10 और कक्षा 1 से 12 के रूप में निर्धारित की गई हैं।

नई शिक्षा नीति-2020 की चौथी वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश की शालाओं में 22 जुलाई से शिक्षा सप्ताह की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। यह गतिविधियां 28 जुलाई तक निरंतर जारी रहेंगी। गतिविधियों के तहत कक्षाओं में लघु नाटिका, कहानी सुनाना, जादुई पिटारा से संबंधित गतिविधियां हो रही हैं। सप्ताह के दूसरे दिन मूलभूत साक्षरता, विद्यार्थियों में पढ़ाई की प्रति रूचि, खिलौना आधारित शिक्षा और फिल्म प्रदर्शन जैसी गतिविधियां होंगी। सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन सभी शालाओं में स्वदेशी खेलों की गतिविधियों को विशेष रूप से आयोजित किया जायेगा। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के मकसद से सांस्कृतिक विविधता पर केन्द्रित भाषा, वेशभूषा, खान-पान, लोकनृत्य और लोकगीतों की जानकारी दी जायेगी। सप्ताह के पांचवे दिन शाला के नजदीक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा। इसी दिन जैविक खेती, पशुपालन, सहकारी समितियों का भ्रमण, मिट्टी, शिल्प और बाँस जैसी साम्रगियों के महत्व के बारे में छात्रों को बताया जायेगा। सप्ताह के छठवें दिन प्रत्येक शाला में ईको क्लब के गठन के साथ ही प्रत्येक शाला में कम से कम 35 पौधे लगाये जायेंगे। छात्रों को इनके सुरक्षा की शपथ दिलाई जायेगी। सप्ताह के सातवें और अंतिम दिन सामूहिक महत्व के प्रयासों को बताने के लिये जागरूकता रैली का आयोजन मुख्य रूप से किया जायेगा।

राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर प्रत्येक गतिविधि में अधिक से अधिक छात्रों की सहभागिता पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सप्ताह के दौरान शालाओं में मौजूद प्रयोगशालाओं में छात्रों की मौजूदगी के साथ गतिविधि आयोजित करने के लिये कहा है।

# सिटी टाइगर

विन्ध्य टाइगर

सीधी, बुधवार 24 जुलाई 2024

8


जिले भर में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नक्शा तरमीम तथा अविवादित नामांतरण के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत किए जा रहे हैं।

## भारत को सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बजट : उप-मुख्यमंत्री

### समावेशी और भविष्योन्मुखी विकास का निरूपण

**रीवा।** उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट 2024-25 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास और भविष्य की दृष्टि से तैयार किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रों को प्रगति की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बजट में ग्रामीण और शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं, उद्योग, और स्टार्ट-अप सहित सभी क्षेत्रों को संतुलित तरीके से प्राथमिकता दी गई है। युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के कई प्रावधान किए गये हैं।

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला है। महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगजन के लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को इस दूरदर्शी और संतुलित बजट के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह बजट भारत को सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 12.7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि - उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 12.7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि कर 89 हज़ार 287 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर 1 लाख 25 हज़ार 638 करोड़ रुपये प्रावधानित हैं।

कौशल विकास और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के कई प्रावधान 4 करोड़ 10 लाख से अधिक युवा लाभान्वित होंगे - उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं को कौशल विकास और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के प्रावधान किए गये है। इन प्रावधानों से 4 करोड़ 10 लाख से अधिक युवा लाभान्वित होंगे। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए विगत माह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गयी थी, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के साथ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के बजट में सशक्त प्रयास किये गये हैं। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में एक करोड़ से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही किसानों को ब्रांडिंग में सहयोग प्रदान करने के भी प्रावधान किए गये हैं।

एमएसएमई को वित्तीय सहायता, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन - आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, सरकार ने सड़क, रेल, और हवाई मार्ग के विस्तार के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह बजट देश के औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता, स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन, और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। %तरुण% श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान एमएसएमई क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करेगा साथ ही रोज़गारों के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

## अविवादित नामांतरण के 1200 प्रकरण किए गए निराकृत

**रीवा।** जिले भर में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नक्शा तरमीम तथा अविवादित नामांतरण के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत किए जा रहे हैं। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा में बी-1 का वाचन किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि अविवादित नामांतरण के विभिन्न तहसीलों में 2579 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से सुनवाई के बाद 1200 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। शेष 1379 प्रकरण 30 दिन की समय सीमा में निराकृत कर दिए जाएंगे। तहसील गुढ़ में 94, सेमरिया में 123, जवा में 169, मनगवां में 146, रायुपर कर्चुलियान में 155, तहसील हुजूर में 56, त्योंथर में 128, सिरमौर में 151 तथा तहसील हुजूर नगर में 178 अविवादित नामांतरण के प्रकरण निराकृत किए गए।

## हवाई अड्डे के आसपास निर्माण कार्यों में लेना होगा ऊंचाई संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र

**रीवा।** रीवा एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट से हवाई सेवा के संचालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार तैयारियाँ की जा रही हैं। इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि रीवा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करते समय ऊँचाई संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। ऊँचाई संबंधी क्लियरेंस प्रमाण पत्र एसडीएम हुजूर द्वारा जारी किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को तथा आयुक्त नगर निगम शहरी आबादी को इस संबंध में सूचित करें।

जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई सेवाओं के संचालन के लिए विमान प्रचालन की रक्षा हेतु ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध नियम 2015 अधिसूचित किए गए थे। इसकी अधिसूचना विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे की 20 किलोमीटर की परिधि में निर्माण कार्यों की ऊंचाई निर्धारित की गई है जिससे विमान सेवाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा न हो। इसलिए निर्धारित परिधि में आने वाले क्षेत्र के निर्माण कार्यों में निर्धारित ऊंचाई का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

### कलेक्टर आज करेंगी वृक्षारोपण कार्य की समीक्षा

**रीवा।** जिले भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है। सभी शिक्षण संस्थाओं, कार्यालय परिसरों, छात्रावासों तथा अन्य उपयुक्त स्थलों पर वृक्षारोपण लगातार जारी है।

## संवेदनशील लेखन समाज का मार्गदर्शन करता है : शुक्ल

### अभिव्यक्ति के चार दशक पुस्तक का किया विमोचन

**रीवा।** उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक समस्याओं पर संवेदनशील लेखन समाज का मार्गदर्शन करता है। कुरीतियों के सुधार के लिए प्रेरित करता है। हमेशा से लेखक और विचारकों ने शासन व्यवस्था को जागरूक किया है, सहयोग प्रदान किया है। ताकि सुशासन की स्थापना हो और जन-सामान्य की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित हो। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के सभागार में संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री प्रलय श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक अभिव्यक्ति के चार दशक का विमोचन किया। उप-मुख्यमंत्री श्री

शुक्ल ने श्री श्रीवास्तव द्वारा उनके अनुभवों को रेखांकित करने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने वेबसाइट और यूट्यूब चैनल जागरूक के लोगो का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस, विधायक श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी, पूर्व सांसद श्री आलोक संजर, वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव सहित जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारी, पत्रकारगण और साहित्यकार उपस्थित थे। पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती चिटनीस ने कहा कि शासकीय ज़िम्मेदारियों के निर्वहन की व्यस्तताओं के साथ अपने मौलिक विचारों को जीवंत रखना और समाज के हित में अनुभव साझा करने का यह प्रयास सराहनीय है। सेवानिवृत्त आईएएस श्री श्रीवास्तव ने कहा जनसंपर्क में प्रचार लेखन कार्य के साथ विचार लेखन का प्रयास सराहनीय है।

## जन सुनवाई में आमजनता के 78 आवेदनों में की गई सुनवाई

**रीवा।** कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में आमजनता के 78 आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई। जन सुनवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले तथा संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने प्रकरणों का निराकरण किया। नायब तहसीलदार विन्ध्या मिश्रा ने भी राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया। जन सुनवाई में सीमांकन, बंटवारा, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, पेंशन के भुगतान, उपचार सहायता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति सहित विभिन्न आवेदनों में सुनवाई की गई।

जन सुनवाई में रामानुज चौरसिया निवासी भीटी ने जमीन

के बंटवारे तथा नामांतरण के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार गुढ़ को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। रेख बड़गईयाँ निवासी रीवा ने जनता कालेज द्वारा उनकी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आवेदन दिया। प्रकरण में तहसीलदार हुजूर को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। भैयालाल साकेत निवासी ग्राम सहिजना ने आम रास्ते से अवैध कब्जा हटाकर रास्ता बहाल करने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार गोविंदगढ़ को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। रावेन्द्र प्रताप सिंह निवासी मढ़ीकला ने सीमांकन के आदेश का पालन कराते हुए उनकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। प्रकरण में तहसीलदार मनगवां को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

जन सुनवाई में शकुंतला शर्मा निवासी रीवा ने सेवानिवृत्त पति जमुना प्रसाद शर्मा के स्वत्वों के भुगतान के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ को आवेदन में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। नीता त्रिपाठी निवासी अनंतपुर ने खसरे में की गई गलत फीडिंग को सुधारने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार हुजूर को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए। राधाकांत मिश्रा निवासी शाहपुर ने उनके शस्त्र लाइसेंस को जिला मऊगंज स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया। प्रभारी अधिकारी शस्त्र शाखा को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बृजलाल तिवारी निवासी ग्राम ओढ़की खुर्द ने नहर के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा देने के लिए आवेदन दिया। एसडीएम हुजूर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

## स्वसहायता समूह को मिला एक लाख से अधिक गणवेश बनाने का आर्डर

### समूह के सदस्यों को हो रही है अतिरिक्त आमदनी

**रीवा।** मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत-चोरगड़ी में लक्ष्मी संकुल स्तरीय संगठन द्वारा लेगिंन एवं गणवेश सिलाई यूनिट स्थापित करते हुए नवाचार किया गया है।

स्वसहायता समूहों को सशक्त करने एवं रोजगार मुहैया कराए जाने हेतु शासन स्तर से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप समूह के आय में लगातार वृद्धि हो रही है। शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क गणवेश वितरण कार्य अन्तर्गत स्वसहायता समूहों को गणवेश सिलाई एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है जिसके तहत कक्षा एक से कक्षा पांच तक अध्ययनरत छात्राओं को गणवेश के साथ-साथ लेगिंन प्रदान की गई है इस हेतु लेगिंन सिलाई का कोई भी साधन समूह के पास उपलब्ध

नहीं था जिससे समूह को मजबूरन महंगे दर पर लेगिंन खरीदने हेतु विवश होना पड़ता था। इस वर्ष स्वसहायता समूह सदस्यों एवं उनके संगठनों के द्वारा जिले में नवाचार करते हुए लेगिंन सिलाई यूनिट स्थापित की गई है और समूह को एक लाख दस हजार लेगिंन का आर्डर अलग-अलग एजेंसियों द्वारा दिया गया। इससे स्वसहायता समूह सदस्यों की आय में वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी को प्रेषित लेगिंन प्रस्ताव भी स्वीकृत किया जा चुका है जिससे समूह सदस्यों में खासा उत्साह है। लक्ष्मी संकुल स्तरीय संगठन द्वारा हाईटेक सिलाई सेंटर की भी स्थापना की गई है जिसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हुए शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वितरण हेतु गणवेश सिलाई का कार्य किया जा रहा है इस कार्य में संलग्न स्वसहायता समूह सदस्यों की आमदनी में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

## रीवा संभाग में 56.37 लाख हितग्राहियों को मिल रहा है खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ

**रीवा।** गरीब परिवारों सहित 29 श्रेणियों में शामिल पात्र परिवार के सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है। रीवा संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 2576 उचित मूल्य दुकानों से हर माह 56 लाख 37 हजार 23 हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इससे रीवा संभाग के 13 लाख 7 हजार 529 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें प्रत्येक सदस्य को पाँच किलो के मान से खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में प्रभारी आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पात्र परिवारों को राशनकार्ड तथा पात्रता पर्ची जारी की गई हैं। इनके आधार पर उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीन के माध्यम से सत्यापित कर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। संभाग के मैहर जिले में 286 उचित मूल्य दुकानों से 6 लाख 17 हजार सात, मऊगंज में 269 दुकानों से 5 लाख 42 हजार 190 तथा रीवा जिले में 655 उचित मूल्य दुकानों से 12 लाख 44 हजार 762 हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। सतना जिले में 536 उचित मूल्य दुकानों से 10 लाख 77 हजार 474, सीधी जिले में 448 उचित मूल्य दुकानों से 10 लाख 52 हजार 994 एवं सिंगरौली जिले में 382 उचित मूल्य दुकानों से 11 लाख 2 हजार 596 हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

## राजस्व महाअभियान में किया जा रहा बी-1 का वाचन

**रीवा।** जिले भर में 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए नियमित सुनवाई की जा रही है। नक्शा तरमीम तथा अभिलेखों में सुधार के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत किए जा रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन कर बी-1 का वाचन किया जा रहा है। साथ ही फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इस क्रम में गत दिवस हुजूर तहसील के ग्राम नयागांव में बी-1 का वाचन किया गया।

इसी तरह ग्राम रजहा में ग्राम सभा में बी-1 का वाचन किया गया तथा फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज किए गए। ग्राम सभा में सरपंच, पंचगण तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। ग्राम सोनारी तथा त्योंथर तहसील के विभिन्न गांवों में विशेष ग्राम सभा में बी-1 का वाचन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लंबित प्रकरणों में ई केवाईसी दर्ज कराई गई। ग्राम पंचायत बरहदी, ग्राम पंचायत घूमा, ग्राम पंचायत कोष्टा, ग्राम पंचायत खजुहा, चोरगड़ी, में भी विशेष ग्राम सभा आयोजित करके बी-1 का वाचन किया गया।

## केंद्रीय बजट 2024-25, अनुसंधान और शिक्षा के लिए संजीवनी

**रीवा।** राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2024-25 का पेश करते समय अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख करोड रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा ऐसी बात कही गई है, साथ ही इस कोष के माध्यम से अनुसंधान के लिए शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बजट मे शिक्षा,रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जिससे अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

## मोदी सरकार के नए बजट में देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्पः जनार्दन

**रीवा।** सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार के नए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह देश, देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया है। वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट हर वर्ग के लिए 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बजट को सर्वसमावेशी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। रीवा सांसद ने कहा कि समाज के हर वर्ग की बेहतरी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए बजट में मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बजट में कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधारों पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा, जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा। भाजपा मऊगंज के जिला अध्यक्ष डॉ राजेंद्र मिश्रा ने देश के आम बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिन चार जातियों युवा, महिला, गरीब और किसानों की बात करते हैं, नए बजट में उनके सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जो महिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। युवाओं से संबंधित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये के लोन का प्रावधान किया गया है।

रीवा नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने केंद्रीय बजट को लोक कल्याणकारी निरूपित करते हुए कहा है कि रोजगार और नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष राहत देने वाला बजट है युवाओं को पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में मिलेंगे। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.53 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 32 फसलों के लिए 109 नई किस्में लाई जाएंगी तथा दलहन एवं तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। बजट में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा की गई है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इससे 63 हजार गांवों में 5 करोड़ आदिवासी भाईयों-बहनों को लाभ होगा।

भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव नेकहा कि नए बजट में देश में अधोसंरचना के विकास के साथ देश के बहुआयामी विकास पर जोर दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।


स्वत्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक राजेन्द्र तिवारी द्वारा एस आर के प्रिंटिंग प्रेस विवि रोड खुटेही रीवा से मुद्रित कर जीडीसी के सामने उत्तरी करौंदिया सीधी से प्रकाशित। संपादक-राजेन्द्र तिवारी, आर.एन.आई नं. 47589/88, डाक पंजीयन : MP/SDL/DN/-30/2015-17, दूरभाष : 09424315633,7389444833